www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 25 अंक : 16 | गोरखपुर, 12 अक्टूबर 2025 रविवार | पृष्ठ : 6 | मूल्य : 2

कफ सिरप काण्ड: ताकि दवा जहर बन फिर से मासूमों की मौत न बने

दो राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से जुड़ी बच्चों की मौत की घटनाएं देश की दवा नियामक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। यह केवल एक चिकित्सा त्रुटि या आकस्मिक दुर्घटना नहीं, बल्कि उस तंत्र की विफलता का प्रतीक है जिस पर जनता अपने जीवन की रक्षा के लिए भरोसा करती है। दवा जैसी जीवनदायी वस्तु में भी जब लालच, लापरवाही या भ्रष्टाचार घुसपैठ कर जाते हैं तो वह अमृत भी विष बन जाता है। बच्चों की मासूम जानें जब घटिया या मिलावटी दवा के कारण चली जाती हैं, तो यह केवल परिवारों की नहीं, बल्कि पूरे समाज की नैतिकता एवं विश्वास की मृत्यु होती है। कफ सिरप में पाए गए विषैले तत्व-जैसे डाइएथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल, पहले भी कई देशों में सैकड़ों बच्चों की जान ले चुके हैं। फिर भी बार-बार ऐसे हादसे होना इस बात का प्रमाण है कि भारत की दवा नियामक व्यवस्था में संरचनात्मक खामियां बनी हुई हैं। सवाल है कि पिछली गलतियों से क्या सीखा गया? भारत में बने कफ सिरप पहले भी सवालों में आ चुके हैं। 2022 में गाम्बिया में कई बच्चों की मौत के बाद डब्ल्यूएचओ ने एक भारतीय कंपनी के कफ सिरप को लेकर चेतावनी जारी की थी। इसके बाद भी कई और जगहों से इसी तरह की शिकायत आई।

दवाओं के उत्पादन में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। करीब 200 देशों में यहां से दवाएं निर्यात होती हैं और जेनेरिक दवाएं सबसे ज्यादा यहीं बनती हैं। इन उपलब्धियों के बीच इन दो प्रमुख राज्यों में कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत शर्मनाक एवं त्रासदीपूर्ण है। इससे स्पष्ट है कि दवा के क्षेत्र में जिस तरह की निगरानी, मानक और सुरक्षा उपायों की जरूरत है, उसमें कोताही बरती जा रही है। दवा के रूप में जहर धडल्ले से मासूमों की मौत का कारण बन रहा है। इस घटना सामने आने के बाद कार्रवाई का दौर भले ही जारी है। दवाएं वापस ली गई हैं, केस दर्ज हुआ है और नैशनल रेगुलेटर अथॉरिटी ने कई राज्यों में जांच की है। इन घटनाओं से साफ है कि दवा निर्माण की प्रक्रिया में कच्चे माल के स्रोत से लेकर तैयार उत्पाद की गुणवत्ता जांच तक हर स्तर पर लापरवाही व्याप्त है। कई कंपनियां लागत घटाने के लिए औद्योगिक ग्रेड के सॉल्वेंट या रसायनों का प्रयोग कर लेती हैं जो मानव उपभोग के लिए निषिद्ध होते हैं। वहीं निरीक्षण और परीक्षण की सरकारी व्यवस्था न केवल कमजोर है बल्कि अक्सर प्रभावशाली कंपनियों के दबाव में निष्क्रिय भी हो जाती है। राज्य और केंद्र स्तर के दवा-नियामक विभागों में पर्याप्त संसाधन और तकनीकी क्षमता का अभाव है, जिससे समय पर निगरानी और सैंपल परीक्षण संभव नहीं हो पाता। जब निरीक्षण औपचारिकता बन जाए और रिपोर्टें खरीद-फरोख्त की वस्तु बन जाएं, तब ऐसी त्रासदियां स्वाभाविक हैं। तमिलनाडु की दवा कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के ह्यकोल्ड्रिफह्ल कफ सिरप के नमूने में 48.6 प्रतिशत डाई एथिलीन ग्लाइकॉल मिला है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार इसकी मात्रा 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह एक खतरनाक इंडस्ट्रियल केमिकल है, जिसका इस्तेमाल गाड़ियों और मशीनों में होता है। इसकी वजह से पीड़ित बच्चों की किडनी फेल हो गई।

इन घटनाओं ने न केवल स्वास्थ्य प्रशासन की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाई है बल्कि भारत की वैश्विक छवि पर भी धब्बा लगाया है। पिछले वर्षों में अफ्रीकी देशों में भी भारतीय सिरप से हुई मौतों के बाद कई देशों ने हमारे फार्मा उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया था। अब घरेलू स्तर पर घटित ऐसी घटनाएं यह दशार्ती हैं कि हमने उन हादसों से कोई सबक नहीं लिया।

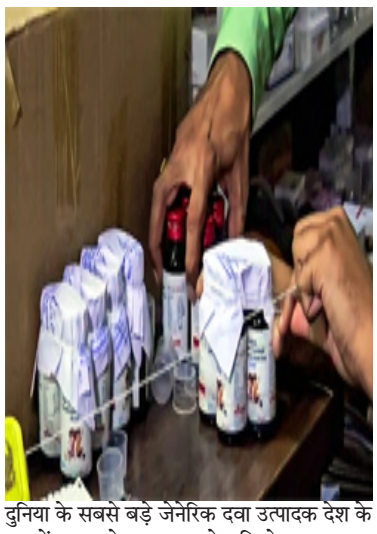

दुनिया के सबसे बड़े जेनेरिक दवा उत्पादक देश के रूप में भारत को यह मानना होगा कि केवल उत्पादन की मात्रा नहीं, बल्कि गुणवत्ता ही हमारी असली ताकत होनी चाहिए। इस संकट का सबसे पीड़ादायक पहलू यह है कि इसका शिकार वे मासूम बच्चे बने जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अभी विकसित नहीं हुई थी और जिनकी जीवन रक्षा का उत्तरदायित्व समाज और राज्य पर है। इन मौतों की नैतिक जिम्मेदारी केवल दोषी कंपनियों पर नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र पर है जिसने नियमन और नैतिकता की आंखें मूंद लीं। दवाओं में मिलावट या गलत प्रमाणपत्र देना कोई साधारण अपराध नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ किया गया घोर अपराध है। इस पर कड़े से कड़ा दंड होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी निमार्ता या अधिकारी ऐसी हरकत करने से पहले सौ बार सोचे।

भारत के फार्मास्युटिकल मार्केट का आकार लगभग 60 अरब डॉलर है। इसका बड़ा हिस्सा छोटी कंपनियों के पास है। सीडीएसीओ ने इस साल अप्रैल की अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ज्यादातर छोटी और मझोली कंपनियों की दवाएं जांच में तयशुदा मानक से कमतर पाई गईं। इस जांच में 68 प्रतिशत एमएसएमई फेल हो गई थीं। इससे पहले, जब केंद्रीय एजेंसी ने 2023 में जांच की, तब भी 65 प्रतिशत कंपनियों की दवाएं सब-स्टैंडर्ड मिली थीं। प्रश्न है कि यह तथ्य सामने आने के बाद आखिर सरकार क्या सोच कर इन दवाओं को बाजार में विक्रय क्यों जारी रहने दिया? क्यों ऐसे हादसे होने दिये जाते रहे? यह आवश्यक है कि दवा उद्योग में कच्चे माल की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित की जाए, हर बैच की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो और दवाओं के मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर के हों। केंद्र और राज्य सरकारों को ड्रग इंस्पेक्टरों की संख्या और प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ानी चाहिए। हर कंपनी के लाइसेंस नवीनीकरण के समय उसकी पिछली गुणवत्ता रिपोर्ट और परीक्षण परिणामों की समीक्षा की जानी चाहिए। जिन कंपनियों ने सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया है, उनके लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिए जाने चाहिए और शीर्ष प्रबंधन को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। केवल प्रशासनिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं, बल्कि इन मामलों में आपराधिक जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी है।

इसके साथ ही चिकित्सा जगत और समाज को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। डॉक्टरों को यह समझना होगा कि शिशुओं को ओटीसी- ऑवर दी कॉउन्टर दवाएं देना कितना खतरनाक हो सकता है। सरकार द्वारा जारी परामर्श और चेतावनियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की जरूरत है। मीडिया को भी सनसनी से ऊपर उठकर जनता को जागरूक करने की जिम्मेदारी निभानी होगी। इन त्रासदियों को केवल समाचार बनाकर भुला देना नहीं, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य-सुधार के आंदोलन में बदलना समय की मांग है। क्योंकि सरकारी अनुमान से इस साल देश का दवा निर्यात 30 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। वहीं, 2030 तक फार्मा मार्केट के 130 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन, इसके साथ चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। दवाओं की जांच और निगरानी अभी तक की कमजोर कड़ी साबित हुई है। केंद्रीय और राज्य की नियामक एजेंसियों को ज्यादा बेहतर तालमेल के साथ, पारदर्शिता, ईमानदारी और ज्यादा तेजी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि यह मामला केवल इकॉनमी या देश की छवि ही नहीं, अनमोल जिंदगियों से जुड़ा है।

अंततः यह घटना हमें याद दिलाती है कि जीवन रक्षा के साधनों में जब नैतिकता का अभाव हो जाता है तो प्रगति की समूची इमारत ध्वस्त हो जाती है। दवा उद्योग में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और मानवीय संवेदनशीलता को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। सरकार और समाज दोनों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी बच्चे की जान किसी घटिया या मिलावटी दवा के कारण न जाए। जब तक दवा बनाने वाला और दवा बांटने वाला अपनी जिम्मेदारी को धर्म, करुणा, विश्वास और ईमानदारी की दृष्टि से नहीं देखेगा, तब तक ऐसी त्रासदियां दोहराई जाती रहेंगी। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम दवा नहीं, दायित्व बनाएं, नियमन नहीं, निष्ठा पैदा करें और इस मानवता विरोधी अपराध के लिए दोषियों को उदाहरण स्वरूप कठोरतम दंड दें ताकि भविष्य में जीवन रक्षक औषधि फिर से विश्वास की प्रतीक बन सके।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गाजीपुर के श्री मंहत रामाश्रय दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भुड़कुड़ा में पहुंचकर परमपूज्य ब्रह्मलीन श्री महंथ रामाश्रय दास जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया और विद्यार्थियों से राष्ट्र एवं संस्कृति के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया।

बालिकाओं की सुरक्षा: भारत में उनके लिए सुरक्षित और सक्षम वातावरण की ओर विषयक संगोष्ठी का आयोजन

प्रधान न्यायाधीश गवई ने डिजिटल दौर में लड़कियों की असुरक्षा परजताई चिंता

नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई ने शनिवार को ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर धमकी और ह्यडिजिटल स्टॉकिंगह्ल के साथ-साथ व्यक्तिगत डेटा और डीपफेक तस्वीरों के कारण लड़कियों के विशेष रूप से संवेदनशील स्थिति में होने को लेकर चिंता जाहिर की।

उन्होंने इस संदर्भ में विशेष कानून बनाए जाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों व नीति निर्धारकों को विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर जोर दिया। 'डिजिटल स्टॉकिंग' इंटरनेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके किसी व्यक्ति को परेशान करना, धमकाना या उसका पीछा करने को कहते हैं।

प्रधान न्यायाधीश ने यूनिसेफ, भारत के सहयोग से उच्चतम न्यायालय की किशोर न्याय समिति (जेजेसी) के तत्वावधान में आयोजित बालिकाओं की सुरक्षाः भारत में उनके लिए सुरक्षित और सक्षम वातावरण की ओर विषय पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श में अपनी चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि संवैधानिक और कानूनी संरक्षण के बावजूद देश भर में अनेक बालिकाओं को अब भी उनके मौलिक अधिकारों और यहां तक कि जीवन-निर्वाह के बुनियादी साधनों से भी वंचित रहना पड़ रहा है। यह असुरक्षा उन्हें यौन शोषण, उत्पीड़न और हानिकारक प्रथाओं तथा अन्य गंभीर जोखिमों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना देती है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल उसके शरीर की रक्षा करना नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा को मुक्त करना है। एक ऐसा समाज बनाना जहां वह सम्मान के साथ अपना सिर ऊंचा रख सके और जहां उसकी आकांक्षाएं शिक्षा और समानता से पोषित हों... हमें उन गहरी जड़ें जमाए हुए पितृसत्तात्मक रीति-रिवाजों का सामना करना होगा और उन पर विजय प्राप्त करनी होगी जो लड़कियों को उनके उचित स्थान से वंचित करते हैं।

रवींद्रनाथ टैगोर की कविता व्हेयर द माइंड इज विदाउट फियर को याद करते हुए न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि इसमें बालिकाओं की सुरक्षा के लिए जो कुछ हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है, उसका सार समाहित है। उन्होंने कहा, ह्यह्रयह सपना तब तक अधूरा रहेगा जब तक हमारे देश में कोई भी लड़की भय में रहेगी - हिंसा के भय में, भेदभाव के भय में, या सीखने और सपने देखने के अवसर से वंचित होने के भय में।

बंगाल में आरजी कर जैसी एक और वारदात अंजाम तक पहुंची

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में एक निजी मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा को अस्पताल परिसर में कथित तौर पर घसीटकर उसके साथ बलात्कार किया गया। यह घटना 2024 के आरजी कर मामले की याद दिलाती है, जिसमें एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। पीड़िता, जो ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है, राजधानी कोलकाता से 170 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्र दुर्गापुर के शोभापुर के पास स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। सूत्रों के अनुसार, छात्रा शुक्रवार रात साढ़े आठ बजे अपने एक पुरुष मित्र के साथ परिसर से बाहर निकली थी। परिसर के गेट के पास एक व्यक्ति उसे कथित तौर पर अस्पताल के पीछे एक सुनसान इलाके में खींचकर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और जाँच शुरू की। पीड़िता को मेडिकल जाँच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों और महिला के साथ आए उसके दोस्त सहित अन्य लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है।

मेडिकल छात्रा के पिता ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें उनकी बेटी के दोस्त ने घटना की सूचना दी। उन्होंने आरोप लगाया, जब मैं वहाँ पहुँचा, तो मेरी बेटी की हालत गंभीर थी और अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने आगे बताया कि उनकी बेटी अपने प्रेमी वासिफ अली के फोन के

बाद फुचका (गोलगप्पे) खाने के लिए कैंपस के बाहर गई थी। पीड़िता के पिता ने बताया, जब वह कैंपस के गेट पर पहुँची, तो वहाँ चार-पाँच लोग मौजूद थे। उनमें से एक ने उसके साथ बलात्कार किया, उसका मोबाइल फोन छीन लिया और उसे वापस करने के लिए 3,000 रुपये माँगे। लड़का उसे छोड़कर भाग गया। उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया।

इस घटना के सामने आने के बाद, पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फ्रंट (हइऊह्र) ने मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की कड़ी निंदा की और इसे एक और डरावनी याद दिलाने वाला बताया कि महिलाएँ (राज्य में) परिसरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। लड़की के लिए न्याय की माँग करते हुए, डब्ल्यूबीडीएफ ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को मामले का संज्ञान लेना चाहिए और न्यायिक जाँच का आदेश देना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने भी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था बार-बार विफल हो रही है।

अयोध्या दीपोत्सव की भव्य तैयारी:

28 लाख दीयों से बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड!

अयोध्या। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बयान में कहा कि शहर में नौवें दीपोत्सव के तहत अयोध्या में सरयू नदी के किनारे 56 घाटों को लगभग 28 लाख दीपों से रोशन किया जाएगा। पहली बार, लक्ष्मण किला घाट भी इस उत्सव में शामिल होगा, जिससे यह उत्सव और भी भव्य हो जाएगा। घाट को 1.25 लाख से ज्यादा दीपों से रोशन किया जाएगा। राज्य सरकार ने बताया कि राम की पैड़ी और चौधरी चरण सिंह घाटों पर लगभग डेढ़ लाख दीये जलाए जाएँगे, जबकि भजन संध्या घाट भी डेढ़ लाख दीयों से जगमगाएगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण, राम की पैड़ी, 15-16 लाख दीयों से जगमगाएगी। पिछले वर्षों में अयोध्या के दीपोत्सव को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है। इस वर्ष, आयोजकों का लक्ष्य 28 लाख दीये जलाकर उस रिकॉर्ड को तोड़ना है। इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार, प्रशासन और स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों की टीमें अथक प्रयास कर रही हैं। सजावट, सुरक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आगंतुकों के आतिथ्य सत्कार के लिए व्यापक तैयारियाँ चल रही हैं। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में दीपोत्सव के नोडल अधिकारी प्रो. संत शरण मिश्र की देखरेख में, महोत्सव के हर पहलू की निगरानी के लिए 22 समितियों का गठन किया गया है। बयान में कहा गया है कि प्रमुख समितियों में समन्वय, अनुशासन, सुरक्षा, दीप गणना, यातायात, स्वच्छता, मीडिया एवं फोटोग्राफी, प्राथमिक चिकित्सा, सजावट, रंगोली, स्वयंसेवकों की पहचान पत्र, और निगरानी एवं नियंत्रण शामिल हैं।

बिहार चुनाव से पहले जदयू में अरुण कुमार की 'घर वापसी'

क्या नीतीश को मिलेगा चुनावी बूस्टर?

जहानाबाद। बिहार चुनाव की तारीखें नजदीक आने के साथ, जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुखर आलोचक रहे, बीते शनिवार (11 अक्टूबर 2025) को जनता दल (यूनाइटेड) (जेडीयू) में फिर से शामिल हो गए। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' और राज्य इकाई के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में उन्हें पार्टी में फिर से शामिल किया गया। पूर्व विधायक अरुण कुमार ने अपनी पार्टी में शामिल होने की घोषणा करते हुए कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मुझे फिर से बिहार की जनता की सेवा करने का अवसर मिला है।

बिहार राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि हम बिहार में फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। अरुण कुमार के साथ उनके कई समर्थक भी शनिवार को जदयू में शामिल हुए। अरुण कुमार का स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' ने कहा, ₹अरुण जी, हम शुरू से ही आपके साथ हैं। आप रास्ते में कहीं बिछड़ गए थे, लेकिन फिर से साथ आ गए हैं, और हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। यह आपका पुराना घर है। आप इस घर में आराम से रह सकते हैं, और आपको जो भी सामान चाहिए, हम उसका ध्यान रखेंगे।

हम इस जदयू में सभी का स्वागत करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अरुण कुमार और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी मगध की धरती पर तूफान लाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने अभी अरुण कुमार और चंदेश्वर चंद्रवंशी को गले मिलते देखा। वे मगध क्षेत्र में तूफान लाएंगे। इससे पहले, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह ने बुधवार को कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सत्ता में वापसी के लिए तैयार है।

पत्रकारों से बात करते हुए ललन सिंह ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हम इसका इंतजार कर रहे थे। 14 नवंबर को बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी।

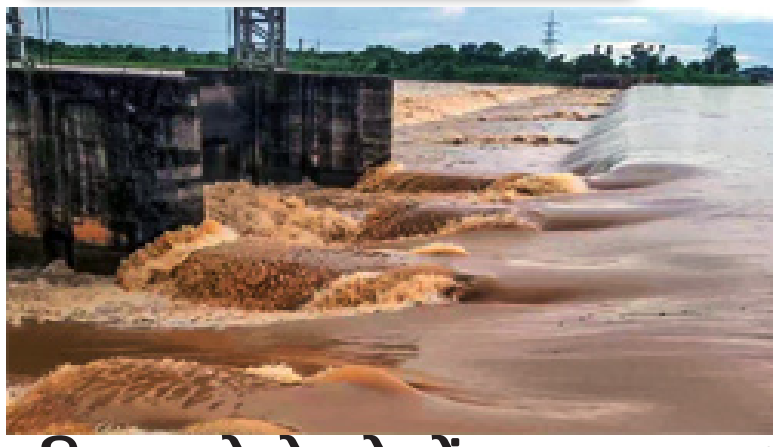

तमिलनाडु के वेल्लोर में बाढ़ का खतरा !

▸ पोन्नई नदी किनारे रहने वालों के लिए रेड अलर्ट जारी

चेन्नई। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के कारण कल्वाकुंटा बांध से पानी छोड़ा गया है। इसी तरह, पोन्नई एनीकट नदी से सुबह 4 बजे तक 6,500 घन फीट पानी छोड़ा गया। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि पानी का प्रवाह और बढ़ सकता है। इसके चलते, वेल्लोर और रानीपेट जिलों में पोन्नई नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीणों को नदी के किनारे न जाने की सलाह दी गई है।

जिले के एक शीर्ष अधिकारी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि गांवों में रहने वाले लोगों को नहाने सहित किसी भी उद्देश्य के लिए नदी का उपयोग नहीं करना चाहिए। वेल्लोर के जिलाधिकारी वी आर सुब्बुलक्ष्मी ने बाढ़ की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में कलावगुंटा बांध से शनिवार सुबह पौने आठ बजे तक लगभग 540 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।

उन्होंने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि पड़ोसी राज्य में बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश को देखते हुए सुबह आठ बजे से पानी का बहाव बढ़ाया जा रहा है। अधिकारी ने कहा, इसलिए पोन्नई नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने और किसी भी उद्देश्य के लिए नदी के पास जाने से बचने की सलाह दी जाती है, चाहे वह स्नान करना हो, कपड़े धोना हो या नदी पार करना हो। इसके अलावा उन्होंने अभिभावकों से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि बच्चे नदी के निकट न जाएं।

वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिनों तक हल्की बारिश होने की संभावना है और इसके बाद राज्य में शुष्क मौसम रहेगा। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह तक कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के कुछ हिस्सों में 30 से 40

किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उप-हिमालयी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह से राज्य में मुख्यतः शुष्क मौसम रहने की संभावना है। पिछले सप्ताहांत उत्तर बंगाल में मूसलाधार बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन और बाढ़ आने से 32 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार को सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक (23 मिलीमीटर) बारिश पश्चिम मेदिनीपुर जिले के कलाईकुंडा में दर्ज की गई। पूर्व मेदिनीपुर के कांथी में 22 मिमी और उत्तर 24 परगना जिले के दमदम में 18 मिमी बारिश दर्ज की गई। आईएमडी के अनुसार, इस अवधि के दौरान उत्तर बंगाल के जिलों में कोई बारिश नहीं हुई।

वाल्मीकि जयंती पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन

वाल्मीकि अवध क्षेत्र के सांस्कृतिक गौरव: आद्या प्रसाद सिंह प्रदीप

कादीपुर (सुलतानपुर)। वाल्मीकि विश्व साहित्य के पहले लोक कवि हैं। उनका काव्य सदैव प्रेरणा देता है। वाल्मीकि अवध क्षेत्र के सांस्कृतिक गौरव हैं।' यह बातें वरिष्ठ साहित्यकार आद्या प्रसाद सिंह प्रदीप ने कहीं। वह अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा रानेपुर गांव में वाल्मीकि जयंती पर आयोजित संगोष्ठी को बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित कर रहे थे।

विशिष्ट अतिथि बलभद्र प्रसाद पाण्डेय ने कहा कि वाल्मीकि साहित्य का अध्ययन कर हम उस समय के समाज के बारे में जान सकते हैं। वाल्मीकि हमारे आदरणीय पूर्वज हैं। विशिष्ट वक्ता राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर ज्ञानेन्द्र विक्रम सिंह रवि ने कहा कि वाल्मीकि भारतीय संस्कृति के पहले प्रचारक हैं। उनका काव्य मानवतावादी काव्य है। महर्षि वाल्मीकि समानता समरसता और सेवा के उत्तम उदाहरण हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के जिलाध्यक्ष मथुरा प्रसाद सिंह जटायु ने कहा कि रामकथा में उपज रहे विवाद के लिए वाल्मीकि रामायण निर्णायक भूमिका निभा सकता है। उस समय की तमाम घटनाएं यह साबित करती हैं कि वाल्मीकि अवध क्षेत्र के महर्षि थे। अध्यक्षता स्वामी दयाल पाण्डेय, संचालन परिषद के जिला महामंत्री डॉ करूणेश प्रकाश भट्ट व आभार ज्ञापन संयोजक पवन कुमार सिंह ने किया।

संस्कृत विश्व की वैज्ञानिक भाषा है:गजेंद्र सिंह शेखावत

वाराणसी। संस्कृत मात्र एक भाषा नहीं, भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को समेटने वाली अमूल्य निधि है जो समस्त भारतीयों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। संस्कृत के ज्ञान के बिना भारत को जानना पूर्ण संभव नहीं है। संस्कृत विश्व की वैज्ञानिक भाषा है। इसकी खास बात यह है कि संस्कृत जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी भी जाती है। ये बातें केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहीं। वह गत बुधवार को संपूणानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 43वें दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने विश्वविद्यालय के ऐतिहासिकता पर चर्चा करते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय में प्रारंभ काल से ही देश-विदेश के छात्र अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए आते रहे हैं। आज भी कई विदेशी छात्र शोध कार्य में संलग्न हैं। भारत वर्ष में संस्कृत विधाओं के संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार के लिए स्थापित यह प्राचीनतम शिक्षा का केंद्र है। यह विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र ही नहीं, भारतीय संस्कृति का दर्पण, दर्शन, भाषा और परंपरा का संरक्षण एवं संवर्धन कर महान ध्येय लेकर अपने साथ चलने वाला एक ऐसा संस्थान है जहां ज्ञान-विज्ञान की परंपरा आज भी जीवित है। भारतीय मनीषियों के साथ-साथ पश्चिम के विद्वानों ने भी यहां सारस्वत साधना की है। इसमें टीएच ग्रिफिथ, जे एम वेलेंटाइन, वेनिस थिबो ने संस्कृत का अध्ययन किया। विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन में पांडुलिपियों के संरक्षण और छायांकन का कार्य गतिमान है। इस ज्ञान को डिजिटल के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। टॉकिंग कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा देवभाषा संस्कृत ही है। भारत में संस्कृत सामान्य बोलचाल की भाषा थी और धीरे-धीरे कालांतर में कर्मकांड तक ही सीमित रह गई थी लेकिन वर्तमान में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हो रहा है। छात्र व छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि यह व्यैक्तिक, शैक्षणिक उपलब्धियों का उत्सव नहीं बल्कि यह भारत की गौरवशाली बौद्धिक परंपरा को समर्पित महान संस्था की विरासत का भी उत्सव है।

डरेंगे नहीं, अंत तक लड़ेंगे आर्यन केस को लेकर बोले समीर वानखेड़े

नई दिल्ली। आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने आर्यन खान की पहली नेटफ्लिक्स सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के निमार्ता शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। वानखेड़े ने आखिरकार इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और अपने द्वारा दायर मुकदमे के बारे में बात की है। अधिकारी ने यह भी खुलासा किया कि उनके परिवार को तब से धमकियाँ मिल रही हैं। 8 अक्टूबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानहानि मामले में नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज दोनों को नोटिस जारी किया। समीर वानखेड़े ने दावा किया कि मानहानि के आरोप द बाड्स ऑफ बॉलीवुड में एक अधिकारी के चित्रण से उपजे हैं, जो उनसे मिलता-जुलता है। वानखेड़े की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को नोटिस जारी किया गया है।

मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने इस मामले के परिणामस्वरूप अपने परिवार को हो रहे उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। उन्होंने एएनआई से कहा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसका मेरे काम या पेशे से कोई लेना-देना नहीं है। अपनी व्यक्तिगत क्षमता में मैंने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मैं अदालती कार्यवाही या इससे जुड़े मुद्दों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है... यह स्वाभिमान, व्यक्तिगत गरिमा और व्यक्तिगत सम्मान का मामला है। आप जो भी व्यंग्य या पैरोडी बनाएँ, अपने लोगों के साथ करें।

उन्होंने आगे कहा कि आज, नशीली दवाओं के दुरुपयोग का मुद्दा हमारे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है, और ऐसी चीजों को उजागर करके, आप न केवल एक व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों का भी अपमान कर रहे हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, और अन्य जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ते हैं... मेरे परिवार का मेरे पेशे से कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें मेरे मामलों, मेरे पेशे से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन वे इस तरह की चीजों का खामियाजा क्यों भुगत रहे हैं? पाकिस्तान, यूएई और बांग्लादेश से नफरत भरे संदेश आ रहे हैं। मैं यह स्वीकार नहीं करूंगा कि मेरी वजह से उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है... हमने नियमित रूप से पुलिस को उन धमकियों के बारे में सूचित किया है जो मेरी बहन और मेरी पत्नी को मिलती रहती हैं।

काशी विद्यापीठ के 47वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल की बेटियों को नसीहत

लिव-इन रिलेशन से दूर रहें, अच्छे निर्णय लें

वाराणसी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 47वां दीक्षांत समारोह बुधवार को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ। कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने समारोह की अध्यक्षता की और विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान कीं। इस अवसर पर उन्होंने समाज और युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए लिव-इन रिलेशन, महिलाओं की सुरक्षा और नैतिक मूल्यों पर विशेष रूप से बात की।

राज्यपाल ने कहा कि लिव-इन रिलेशन का चलन बढ़ रहा है, लेकिन यह बेटियों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। मैं बेटियों से कहना चाहती हूं, ऐसा निर्णय कभी मत लीजिए जो जीवन को बर्बाद कर दे। मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, जहां महिलाएं शोषण की शिकार हुईं और लिव-इन पार्टनर उन्हें छोड़कर चले गए। राज्यपाल ने बताया कि हाल ही में उन्होंने 40 बेटियों से मुलाकात की थी, जिनमें से कई ने अपने परिजनों पिता, मामा, काका या पड़ोसी पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। इन बेटियों ने साहस दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और दोषियों को जेल भिजवाया। उन्होंने कहा कि ह्लइन बच्चियों की हिम्मत देखकर मुझे गर्व हुआ, लेकिन यह भी पीड़ा हुई कि समाज में ऐसे हालात क्यों हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि एक हाईकोर्ट के जज ने उनसे पॉक्सो एक्ट से जुड़ी परेशानियों पर चर्चा की और नेपाल आदि देशों में रह रही बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। इस पर राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजकर ऐसे बच्चों की पहचान करने और मदद करने के निर्देश दिए।

समारोह के दौरान राज्यपाल ने शराब और ड्रग्स की समस्या पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, दो हॉस्टलों के बीच शराब की बोतलें और ड्रग्स के पैकेट मिलना अत्यंत गंभीर बात है। इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। दीक्षांत समारोह में कुल 101 विद्यार्थियों को 103 गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। इस बार स्नातकोत्तर वर्ग में तीन ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को भी उपाधि दी गई। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री प्रोफेसर सरोज चूड़ामणि उपस्थित रहीं।

▸ राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता विषयक प्रबुद्धजन संवाद संगम का आयोजन

भारत की आत्मा के पुनर्जागरण का प्रतीक : सीएम योगी

गाजीपुर। सीएम योगी ने कहा कि भारत की पहचान उसकी आध्यात्मिक चेतना में है और जब तक भारत का नागरिक अपनी आध्यात्मिकता और राष्ट्रीयता के भाव से कार्य करेगा, तब तक देश को विश्वगुरु के रूप में स्थापित होने से कोई नहीं रोक सकता। सीएम योगी शनिवार को गाजीपुर स्थित सिद्धपीठ श्री हथियाराम मठ परिसर में आयोजित राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता विषयक प्रबुद्धजन संवाद संगम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें भगवती मां परम्बा बुढ़िया देवी के दर्शन और 900 वर्ष पुरानी संन्यासी परंपरा के इस सिद्ध पीठ में पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी भवानी नंदन यतिजी महाराज के सानिध्य में उपस्थित होने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि यह पीठ न केवल अध्यात्म का केंद्र है, बल्कि लोकमंगल और राष्ट्रीय एकता का भी सशक्त माध्यम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राम मंदिर निर्माण केवल एक धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि भारत की आत्मा के पुनर्जागरण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जब करोड़ों रामभक्तों ने संकल्प लिया था ह्यराम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगेह्व, तब लोगों ने इसे असंभव माना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और पूज्य संतों के आशीर्वाद से यह संकल्प अब साकार है।

सीएम योगी ने कहा कि 2020 में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने से लेकर 2024 में भगवान श्रीराम के अपने गर्भगृह में विराजमान होने तक की यात्रा भारत की आस्था, एकता और संकल्प शक्ति की मिसाल है। उन्होंने बताया कि अयोध्या में चारों द्वारों का नाम चार प्रमुख आचार्यों शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य और माधवाचार्य के नाम पर रखा गया है। सीएम ने रामायण की कथाओं से प्रेरणा लेते हुए अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को महर्षि वाल्मीकि के नाम, राम मंदिर परिसर में सप्त ऋषियों व तुलसीदास की प्रतिमाएं, गिद्धराज जटायु की मूर्ति और निषादराज के नाम पर रैन बसेरा बनाने का भी उल्लेख किया। वनवास के दौरान सबसे पहले सहयोग करने वाले निषादराज को सम्मान मिला है।

मतंग ऋषि की शिष्या शबरी ने राम भक्ति के लिए जीवन समर्पित किया, जिनके नाम पर भोजनालय बन रहे हैं। ऋषि परंपरा की भविष्यवाणी से प्रेरित होकर हम गाजीपुर मेडिकल कॉलेज को विश्वामित्र के नाम पर समर्पित किया है। यह भारत की एकता में विविधता की झलक है। यह दिखाता है कि दक्षिण से उत्तर तक, भारत एक ही आध्यात्मिक सूत्र में बंधा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे मठ और मंदिर केवल उपासना के स्थान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता के आधार स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि जब समाज में जाति या संप्रदाय के नाम पर वैमनस्य फैलाने की कोशिश होती है, तब यही मठ और संत समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। इतिहास उठाकर के देखिए कि जब भी हम बंटे थे तो कटे थे, और जब एक थे तो नेक थे।

सीएम योगी ने मंच से वीर अब्दुल हमीद और महावीर चक्र विजेता राम उग्रह पांडेय के परिवारों का सम्मान करते हुए कहा कि गाजीपुर की धरती ने देश को असंख्य वीर सपूत दिए हैं। गहमर गांव देश का सबसे बड़ा सैनिक ग्राम है यह इस जनपद का गौरव है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने जो कहा है, वही किया है और जो कहा है, उतना ही बोला है। उन्होंने कहा कि संस्कृत शिक्षा के प्रसार, धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार और गाजीपुर को पर्यटन व अध्यात्म केंद्र के रूप में विकसित करने की योजनाएं तेजी से प्रगति पर हैं। संतों की साधना भूमि पर विकास कार्यों का उद्देश्य केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक उत्थान भी है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार की नीति ह्यपरित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्ह्व के सूत्र पर आधारित है। सज्जनों का संरक्षण और दुष्ट प्रवृत्तियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ही सरकार का धर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत तभी सशक्त बनेगा, जब हर नागरिक अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत रखे और भौतिक प्रगति को उसी आधार पर जोड़े। उन्होंने कहा कि आस्था और विकास का संगम ही नया भारत बनाएगा। हमारी परंपरा हमें केवल भक्ति नहीं, बल्कि कर्म और राष्ट्रधर्म की शिक्षा देती है।

बस की चपेट में आने से बच्ची की मौत

राजाजीनगर, बेंगलुरु। बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (बीएमटीसी) की बस की चपेट में आ जाने से शनिवार को नौ वर्षीय एक लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पीड़ित लड़की की पहचान भुवना के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, राजाजीनगर में पंचजन्य विद्या पीठ स्कूल के पास अपनी दो बहनों के साथ सड़क पार करते समय लड़की को बीएमटीसी बस ने कथित तौर पर टक्कर मार दी।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उसके सिर में गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया और उसे पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।

सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी 'शिवभारत गौरव' से सम्मानित

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वरिष्ठ समाजसेवी और दक्षिण दिल्ली के लोकसभा सदस्य रामवीर सिंह विधूड़ी जी को आज उनके छह दशक के राजनीतिक और सामाजिक सफर के सम्मान में 'शिवभारत गौरव' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें मराठा समन्वय परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश पाटील, पटेल मैत्री समिति के अध्यक्ष इंजी. आर एन राय, और महासचिव पातीराम गंगवार, इंटरनेशनल जिजाऊ ब्रिगेड के मीडिया संयोजक संयुक्ता देशमुख ने संयुक्त रूप से प्रदान किया। सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी से यह मुलाकात आगामी 2 नवंबर को आयोजित देश के प्रथम उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री तथा संविधान सभा की मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष बैरिस्टर सरदार वल्लभभाई पटेल जी की जयंती समारोह के निमंत्रण हेतु की गई थी।

1970 में विद्यार्थी आंदोलन से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने अपने राजनीतिक जीवन के पहले दशक में ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त कर लिया था। वह दिल्ली विधानसभा में चार बार सदस्य रहे और विपक्ष के नेता

की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। उन्हें लोकप्रतिनिधि या लोकनेता कहा जाना चाहिए, जो हमेशा लोगों के बीच रहकर, मेल-मुलाकातों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनका दिनक्रम लोगों से मुलाकात में ही बीतता है। उनके आवास पर आने-जाने वाले आगंतुकों के लिए कम से कम एक समय में 100-150 लोगों की आसन व्यवस्था बनी रहती है, जो उनके व्यापक जनसंपर्क का परिचायक है।

आज की मुलाकात में सांसदश्री से देश के स्वराज्य आंदोलन और इसकी प्रेरणा स्रोतों पर विस्तार से चर्चा हुई। स्वराज्य प्रेरिका जिजाऊ माँ साहेब, स्वराज्य संकल्पक महाराज शहाजी राजे, और भारतीयों के स्वराज्य निमार्ता छत्रपती शिवाजी महाराज के योगदान पर बात हुई। 'स्वराज्य जनक परिवार' प्रतिमा से परिचित कराते हुए बताया गया कि भारतीयों को मौलिक अधिकारों का स्वराज्य सर्वप्रथम शिवाजी महाराज से कैसे मिला। स्वराज्य निर्माण की सफलता से स्वाभिमान से प्रज्वलित भारतीयों को अंग्रेजों से आजादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में सहजता से भाग लेने का हुनर मिला। यह भी अवगत कराया गया कि 1947 की स्वतंत्रता प्राप्ति तक स्वतंत्रता सेनानियों की जो लंबी शृंखला देश को मिली, उसका मूल प्रेरणा स्रोत छत्रपती शिवाजी महाराज का स्वराज्य आंदोलन ही है। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय का नामकरण भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय किए जाने हेतु एक निवेदन भी प्रस्तुत किया।

वित्त मंत्री और सीएम योगी ने बृहस्पति कुंड का किया अनावरण किया

अयोध्या। भगवान श्रीराम की पावन नगरी अयोध्या में बुधवार को एक ऐतिहासिक क्षण आया जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दो दिवसीय दौरे पर पहुँचीं। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उनका भव्य स्वागत किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जब उनका काफिला होटल रेडिसन पहुँचा, तो पारंपरिक धुनें गूंज उठीं और फिर वे अपने निर्धारित कार्यक्रम शुरू करने लगीं। केंद्रीय मंत्री की यात्रा टेढ़ी बाजार स्थित बृहस्पति कुंड में एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करेगी, जहां वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तीन महान दक्षिण भारतीय संगीतकारों, संत त्यागराज स्वामीगल, पुरंदर दास और अरुणाचल कवि की मूर्तियों का अनावरण करेंगी।

बृहस्पति कुंड परिसर में स्थापित ये प्रतिमाएँ भारत की संगीत, भक्ति और कलात्मक विरासत के शाश्वत प्रतीक हैं। इन संत-संगीतज्ञों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत में दिव्य भक्ति का संचार किया और इसे राष्ट्र की संस्कृति का आध्यात्मिक सार बना दिया। भक्ति और धर्म की भूमि अयोध्या में इनकी स्थापना, उत्तर और दक्षिण भारतीय परंपराओं की एकता का एक उल्लेखनीय प्रमाण है।

घूँघट की बगावत

12 अक्टूबर 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

म.मो.मा. प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जीआईएएन में शामिल

गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की प्रतिष्ठित योजना ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स (जीआईएएन) में शामिल कर लिया गया है। इस नेटवर्क से जुड़ने के बाद एमएमएमयूटी में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं और शिक्षकों को परिसर में आमंत्रित कर पाना संभव हो सकेगा। कंप्यूटर साइंस विभाग के डॉ. श्वेत केतु को इस परियोजना का संयोजक नामित किया गया है। तकनीकी शिक्षा, नवाचार व अनुसंधान की दिशा में प्रयासरत एमएमएमयूटी के लिए इस उपलब्धि को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष विभिन्न चरणों में अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त शोधकताओं और शिक्षकों को अपने परिसर में अल्पकालिक पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं, विशेषज्ञ व्याख्यानों के लिए आमंत्रित किए जाने के लिए सदस्य विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय को प्रत्येक चरण में दो चुनिंदा प्रस्तावों की स्वीकृति मिलती है। योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय ख्याति के विद्वानों को आमंत्रित करने के लिए मानदेय सहित आठ से 12 हजार डॉलर तक भुगतान का प्रावधान है। देश के प्रसिद्ध विद्वानों को भी इसके तहत आमंत्रित किया जा सकता है। ख्यातिलब्ध विद्वानों के विश्वविद्यालय में आने से छात्रों और शिक्षकों को वैश्विक स्तर की विशेषज्ञता एवं अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस विषय में प्रो. जेपी सैनी, कुलपति, एमएमएमयूटी के अनुसार जीआईएएन प्लेटफॉर्म से जुड़ना विश्वविद्यालय के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अनुसंधान एवं नवाचार आधारित शिक्षा के नए अवसर प्रदान करेगा। यह विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर अग्रणी संस्थानों की श्रेणी में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा।

विष्णु महायज्ञ की तैयारियां शुरू, निकली कलश यात्रा

गोरखपुर। महानगर के असुरन चौक स्थित विष्णु मंदिर में रामलीला और विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सोमवार को मानस उत्थान समिति की तरफ से विष्णु मंदिर से जन जागरूकता के लिए कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में लोग पीला वस्त्र पहनकर आगे चल चल रहे थे।

सीएम ने की श्रद्धांजलि यू.पी. सिंह के नाम

गोरखपुर। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष रहे, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो.यूपी सिंह की स्मृति में गत गुरुवार शाम गोरखनाथ मंदिर स्थित पर्यटन सुविधा केंद्र परिसर में श्रद्धांजलि अर्पण और ब्रह्मभोज का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रो. यूपी सिंह के चित्र पर श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए शिवावतार गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना की और स्व.सिंह के परिजनों के साथ आत्मीय संवाद किया।

सीएम योगी वनटांगिया ग्रामवासियों संग मनाएंगे दीपोत्सव

गोरखपुर। हर वर्ष की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली के पावन पर्व पर वनटांगिया ग्रामवासियों के साथ दीपोत्सव मनाएंगे। मुख्यमंत्री आगामी 20 अक्टूबर को जंगल तिनकोनिया नंबर-3 वनटांगिया गांव पहुंचेंगे, जहां वे ग्रामीणों के साथ दीप जलाकर, मिठाई बांटकर और उपहार वितरित कर दीपावली की खुशियाँ साझा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का वनटांगिया गांव के लोगों से विशेष लगाव है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियाँ जोरों पर हैं। बता दें कि सांसद रहते हुए भी मुख्यमंत्री प्रत्येक दिवाली में वनटांगिया गांव में जाते रहे हैं। वनटांगियों को सामान्य नागरिक जैसा हक दिलाने की लड़ाई शुरू करने वाले सीएम योगी ने वर्ष 2009 से वनटांगिया समुदाय के साथ दीपोत्सव मनाने की परंपरा शुरू की। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सीएम योगी इस परंपरा का निर्वाह करना नहीं भूलते हैं। वे बच्चों को मिठाई, कॉपी-किताब और आतिशबाजी का उपहार देते हैं।

बाल मरीज के भोजन में मिला कॉकरोच, हुई जांच दी चेतावनी

- मेस संचालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना
- रोगियों के भोजन की निगरानी डॉक्टरों की एक कमेटी कर रही
- मरीजों से भी लिया जा रहा भोजन और नाश्ते के संबंध में फीडबैक

गोरखपुर। एम्स के बाल रोग विभाग में भर्ती एक बच्चे के भोजन में कॉकरोच मिला। देवरिया निवासी इस बच्चे के परिजनों ने भोजन कराते समय यह देखा, जिसके बाद उन्होंने एम्स प्रशासन से शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. विभा दत्ता ने जांच कराई और मेस संचालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। भविष्य में ऐसी कमी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

ज्ञानवर्धक सूत्र बताते हैं कि एम्स में भर्ती मरीजों को नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने एक मेस संचालक के साथ करार किया है। निर्धारित समय पर डॉक्टरों द्वारा तय खाद्य पदार्थ मरीजों को दिए जाते हैं। यह घटना लगभग पांच दिन पहले की है, जब बाल रोग विभाग में भर्ती बच्चे के लिए मेस कर्मचारी भोजन लेकर पहुंचे थे। परिजनों ने जब बच्चे को भोजन कराना शुरू किया तो उसमें कॉकरोच दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी वार्ड कर्मचारियों और नर्सिंग ऑफिसर को दी।

एम्स गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. विभा दत्ता ने बताया कि रोगियों के भोजन की निगरानी डॉक्टरों की एक कमेटी कर रही है। भोजन की नियमित जांच कराई जाती है और संचालक को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में गड़बड़ी पर कार्रवाई के लिए जांच का पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। मरीजों से भी भोजन और नाश्ते के संबंध में फीडबैक लिया जा रहा है, जिसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है।

▸ राष्ट्रीय शिक्षा नीति भाषायी संदर्भः चुनौतियां एवं समाधान विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं के उन्नयन पर जोर दे रही: प्रो. रामदेव शुक्ल

गोरखपुर (जीकेबी)। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी व आधुनिक भारतीय भाषा तथा पत्रकारिता विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. रामदेव शुक्ल ने कहा कि भाषा के बिना शिक्षा की कल्पना अधूरी है। मातृभाषा के माध्यम से ज्ञान का संवहन ही भारतीय शिक्षा की आत्मा है।

प्रो. शुक्ल शनिवार को महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल धूसड़ के हिंदी विभाग व हिंदुस्तानी अकादमी, प्रयागराज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भाषायी संदर्भः चुनौतियां एवं समाधान विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रो. शुक्ल ने कहा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने के उद्देश्य से बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं के उन्नयन पर जोर दे रही है। इसमें मातृ भाषाओं के साथ त्रिभाषा फामूर्ला के उन्नयन के अनेक प्रावधान सन्निहित हैं, जो भली-भांति अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सतत क्रियाशील हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में बहुभाषावाद को भी प्रोत्साहित कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भाषाई संदर्भ पर यदि विचार करें तो यह प्रत्येक विद्यार्थी को तीन भाषाएं सीखने को प्रेरित कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वास्तव में मातृभाषा सहित बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और भारतीय भाषाओं को जीवंत बनाए रखने का महनीय कार्य कर रही है। देश का शीर्ष नेतृत्व इसके लिए साधुवाद एवं प्रशंसा का

पात्र है। राष्ट्रीय संगोष्ठी में उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि रांची विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. जंगबहादुर पाण्डेय ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केवल एक शैक्षणिक दस्तावेज नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और भाषा की पुनर्स्थापना का माध्यम है। शिक्षा मातृभाषा में मिलेगी तो विद्यार्थी का व्यक्तित्व अधिक सशक्त और रचनात्मक बनेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा के महत्व को बहुविध स्वीकार किया गया है और स्कूली शिक्षा में एक अहम बदलाव के रूप में मातृभाषा को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि भाषा केवल किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, अपितु वह किसी देश की अस्मिता की पहचान है। जैसे अंग्रेजी से इंग्लैंड की, चीनी से चीन की और रूसी से रूस की वैश्विक पहचान बनी है, वैसे ही हिंदी से भारत की वैश्विक पहचान बनेगी। भारत की राजभाषा हिंदी, भारत मां के माथे पर बिंदी के समान है।

प्रो. पाण्डेय ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन से भारत के प्रतिभावान विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल होगा और भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा।

विशिष्ट अतिथि केंद्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली के प्रो. धनजी ने कहा कि भाषा राष्ट्र की पहचान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुभाषिकता की अवधारणा भारत की विविधता को एक सूत्र में बांधने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि भाषा कभी अकेली नहीं चलती, उसके साथ संस्ति भी चलती है। आज के जेनझजी युवा अपनी भाषा और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में मातृभाषा में शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति और संस्कारों का संवाहक भी है। इसलिए ऐसी संगोष्ठियां समय की मांग हैं, जहां शिक्षा के साथ संस्कृति का भी संगम हो सके। राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में स्वागत संबोधन महाविद्यालय के प्राचार्य डा. प्रदीप कुमार राव ने कहा कि यह महाविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को अपनाने में आगे और संवेदनशील रहा है। इस महाविद्यालय की स्थापना ही राष्ट्रीयता के विचारों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति के संबंध में भाषाई संदर्भ एक महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर मंथन से निकलने वाले निष्कर्ष मार्गदर्शक होंगे। संगोष्ठी की संयोजिका डॉ. आरती सिंह ने प्रस्ताविकी प्रस्तुत की।

पतियों की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने रखा करवा चौथ का व्रत

गंगा जमुनी तहजीब की प्रतीक है उर्दू भाषा : पूनम टंडन

गोरखपुर। उर्दू के प्रख्यात, स्कॉलर और आलोचक प्रो. असगर अब्बास की स्मृति में शहर की मारुफ संस्था यास्मीन शरीफ वेलफेयर सोसाइटी और फरदीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी की ओर से एमएस-ाआई इंटर कालेज, बाख्शीपुर के सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसके मुख्य अतिथि डीडीयू की कुलपति प्रो. पूनम टंडन मौजूद रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता महात्मा गांधी अंतर राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति प्रो. चितरंजन मिश्र ने किया।

कुलपति टंडन ने कहा कि-उर्दू भाषा हिंदुस्तान की गंगा-जमुनी तहजीब का प्रतीक है। नई तकनीक के साथ-साथ समाज को भाषा, साहित्य और भारतीय ज्ञान परंपरा की आवश्यकता है। मुख्य वक्ता उर्दू विभाग लखनऊ विश्व विद्यालय के प्रो. अब्बास

राजा-नय्यर रहे। संगोष्ठी को डीडीयू के उर्दू विभागाध्यक्ष प्रो. राजवंत राव, प्रो. चितरंजन मिश्र, डॉ. दुष्यंत सिंह, डॉ. कमलेश त्रिपाठी, कामरान खान, प्रो. असगर अब्बास, डॉ. नुजहत फातमा, अब्दुल्ला चिश्ती, मु. तौफीक और मुख्तार अहमद ने संबोधित किया।

कार्यक्रम का संचालन डॉ.कलीम कैंसर, और स्वागत संबोधन डॉ. अशफाक अहमद ने किया।

कार्यक्रम के दौरान. डॉ. फरीद कमर सरवत जमाल नसीम सलेमपुरी सलीम मजहर आदि ने अपने कलाम सुनाएं। साथ ही साथ - मुहम्मद आतिफ, इंकलाब अफजल खान, इरफान सिद्दीकी, डॉ. मुहम्मद अशरफ, डॉ. ताजवर, डॉ. महबूब हसन, डॉ. नुसरत अलीक, डॉ. ओबेदुल्ला चौधरी, महबूब सईद हाफिज नसीरूददीन, और रोशन सिददीकी को सम्मानित किया।

गोरखपुर। कवि शोधकर्ता और इतिहासकार डॉ. राजवंती को गत रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान वर्ष - 2085 के आयाम सम्मान से सम्मानित किया गया। एमएसआई इंटर कालेज, बख्शीपुर के पुस्तकालय भवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. चंद्रभूषण अंकुर ने तथा संचालन अजय कुमार सिंह ने किया।

पांच दिवसीय रंग महोत्सव का हुआ आग़ाज

हास्य नाटक आंख मिचौली का मंचन

गोरखपुर। यूपी के गोरखपुर में पांच दिवसीय रंग महोत्सव का गत दिनों शनिवार को आगाज हुआ। महोत्सव का उद्घाटन गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने किया। महोत्सव के पहले दिन महोत्सव के मंच से प्रिज्म थिएटर सोसाइटी मुंबई के मशहूर नाटक आंख मिचौली का मंचन किया गया। इसमें मशहूर अभिनेत्री रश्मि देसाई और अभिनेता परितोष त्रिपाठी के अभिनय को उपस्थित दर्शकों ने खूब सराहा। इस दौरान बाबा योगी गंभीर नाथ प्रेक्षागृह पूरी तरह नाट्यमंचन देखने वालों से खचाखच भरा रहा. इस आयोजन में प्रवेश भी निशुल्क था जिसमें गोरखपुर के नाटक प्रेमियों ने बढ़कर हिस्सा लिया।

आयोजक संस्था अभियान थिएटर ग्रुप के निदेशक श्रीनारायण पांडेय ने बताया कि पहले दिन हास्य आधारित नाटक में दिखाया गया कि अजय नाम का पात्र घर में भीगी बिल्ली बना रहता है। पत्नी के सामने वह बेबस नजर आता है। अपने नाम के सदैव विपरीत ईर्ष्या और ढोंग का मारा अजय एक बार अपनी पुरानी साथी नैना से टकरा जाता है। दोनों के बीच पुराना प्यार पनप जाता है। नैना के कालू पति उस पर हमेशा शक करते हैं। उधर अजय की बेहद चतुर और समझदार पत्नी संध्या भी इसे लेकर सक्रिय हो जाती है। आंख मिचोली और तकरार के साथ कहानी अंजाम तक पहुंचती है। श्रीनारायण पांडेय ने बताया कि नाटक का रोचक संवाद दर्शकों को खूब गुदगुदाया। मशहूर कलाकारों से सजा मंच नाट्य मंचन को देखने के लिए लोगों को मजबूर किया। आयोजन के पहले दिन प्रस्तुत आंख मिचौली हास्य नाटक में अभिनेता परितोष त्रिपाठी और रश्मि देसाई के अभिनय क्षमता को लोगों ने खूब सराहा।

उच्च गुणवत्तायुक्त ही नहीं टिकाऊ और रंगबिरंगी होंगी सड़कें

गोरखपुर। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (सीएम ग्रिड) योजना के तहत बनाई जाने वाली सड़क न सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाली और टिकाऊ होगी बल्कि रंग बिरंगी भी होगी। इस सड़क को तीन रंगों लाल, आसमानी और भूरे रंग से रंगा जाएगा।

इसके लिए रोलर ब्रश का इस्तेमाल होगा। रंग की गारंटी एक साल की होगी, जिसे फिर से आसानी से रंगा जा सकेगा। ट्रायल के तौर पर इसकी शुरूआत सीएम ग्रिड फेज-1 के तहत राप्तीनगर में बन रही सड़क से होगी। इसके अलावा सड़क के दोनों ओर की दीवार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और महापुरुषों की पेंटिंग भी बनाई जाएगी।

ज्ञानवर्धक सूत्र बताते हैं कि सीएम-ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) के तहत प्रस्तावित शहर की पहली स्मार्ट सड़क अब बेंगलुरु जैसी दिखने लगी है। सड़क का लगभग 100 मीटर हिस्सा पूरी तरह तैयार कर लिया गया है।

इस सड़क के दोनों ओर पैदल और साइकिल यात्रियों के लिए छह इंच ऊंचे फुटपाथ बनाए जा रहे हैं। सड़क के नीचे नाली, बिजली के तारों के लिए डक्ट, पीने के पानी और गैस की पाइपलाइन बिछाने का काम भी पूरा हो चुका है।

इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसी भी

तकनीकी खराबी पर सड़क खोदनी नहीं पड़ेगी और यातायात प्रभावित नहीं होगा। सड़क पर हरियाली बढ़ाने के साथ ही दोनों ओर की दीवार पर महापुरुषों और गोरखपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंटिंग बनाई जाएगी। फुटपाथ पर लोगों के बैठने के लिए बेंच भी लगा दिए गए हैं।

योजना के तहत राप्तीनगर वार्ड के शाहपुर क्षेत्र में तीन सड़कों का निर्माण 44.88 करोड़ रुपये की लागत

ट्रायल के तौर सीएम ग्रिड फेज-वन के तहत बन रही सड़क को रंग-बिरंगा भी बनाया जाएगा। 100 मीटर के पैच से इसकी शुरूआत होगी। बेहतर परिणाम के आधार पर पूरी सड़क को ऐसा ही रूप दिया जाएगा।

अमित कुमार शर्मा,
मुख्य अभियंता,
नगर निगम गोरखपुर

से हो रहा है। इसमें शाहपुर थाना से रिद्धि अस्पताल तक 510 मीटर लंबी और 24 मीटर चौड़ी सड़क, मेडिकल कालेज रोड पर दूरदर्शन आवास से ब्रदर्स बेकरी तक 471 मीटर लंबी और 18 मीटर चौड़ी सड़क और राजीवनगर कुआं से राप्तीनगर विद्युत कार्यालय तक 1417 मीटर लंबी व 18 मीटर चौड़ी सड़क शामिल है। ये तीनों सड़कें आपस में जुड़ी होंगी। मार्च 2026 तक इनका निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

घूँघट की बगावत

12 अक्टूबर 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

समाज में परिवर्तन की वाहक बनें बालिकाएं

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय पालन दिवस है। 11 अक्टूबर 2012 को पहली बार बालिका दिवस मनाया गया था। तब से हर वर्ष 11 अक्टूबर को पूरी दुनिया में इसे मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस दुनिया भर में लड़कियों द्वारा उनके लिंग के आधार पर सामना की जाने वाली लैंगिक असमानता के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। इस असमानता में शिक्षा, पोषण, कानूनी अधिकार, चिकित्सा देखभाल और भेदभाव से सुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और जबरन बाल विवाह जैसे क्षेत्र शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 की थीम है- मैं लड़की हूं, मैं बदलाव का नेतृत्व करती हूं। संकट की अग्रिम पंक्ति में लड़कियां। यह थीम संकट की परिस्थितियों में लड़कियों की दृढ़ता, नेतृत्व और सशक्त भूमिका पर केंद्रित है। यह थीम उन चुनौतियों पर प्रकाश डालती है जिनका सामना बालिकाएं करती हैं। यह थीम बालिकाओं को केवल संकट के शिकार के रूप में नहीं बल्कि परिवर्तन के वाहक के रूप में पहचानने पर जोर देती है। यह थीम शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में निवेश का आह्वान करती है ताकि वे बेहतर और समावेशी दुनिया का निर्माण कर सकें। आज हर क्षेत्र में बालिकाओं के आगे बढ़ने के बावजूद अनेकों कुरीतियों की शिकार हैं। ये कुरीतियां उनके आगे बढ़ने में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। पढ़े-लिखे लोग और जागरूक समाज भी इस समस्या से अछूता नहीं है। देश में आज भी प्रतिवर्ष लाखों लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही कोख में मार दिया जाता है। आज भी समाज के अनेक घरों में बेटा, बेटी में भेद किया जाता है। बेटियों को बेटों की तरह अच्छा खाना और अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है। समाज में आज भी बेटियो को बोझ समझा जाता है। भारत में हर साल तीन से सात लाख कन्या भ्रूण नष्ट कर दिये जाते हैं। इसलिए यहां महिलाओं से पुरुषों की संख्या 5 करोड़ ज्यादा है। समाज में निरंतर परिवर्तन और कार्य बल में महिलाओं की बढ़ती भूमिका के बावजूद रूढिवादी विचारधारा के लोग मानते हैं कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होगा और बेटी हुई तो वह अपने घर चली जायेगी। बेटा अगर मुखाग्नि नहीं देगा तो कर्मकांड पूरा नहीं होगा। पिछले कुछ वर्षों में देश में जन्म के समय लिंगानुपात में बढ़ोतरी होना शुभ संकेत हैं। संसद में एक सवाल का जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने बालिकाओं के अधिकारों को स्वीकार करने के लिए जनता की मानसिकता को बदलने की दिशा में सामूहिक चेतना जगाई है। यह राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) में 12 अंकों के सुधार के रूप में परिलक्षित होता है। जो कि 2014 में 918 था। जबकि 2023-24 में 12 अंक बढ़कर 930 हो गया। हमारे देश में यह एक बड़ी विडंबना है कि हम बालिका का पूजन तो करते हैं लेकिन जब हमारे खुद के घर बालिका जन्म लेती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। देश में सभी जगह ऐसा देखा जा सकता है। देश के कई प्रदेशों में तो बालिकाओं के जन्म को अभिशाप तक माना जाता है। लेकिन बालिकाओं को अभिशाप मानने वाले लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि वह उस देश के नागरिक हैं जहां रानी लक्ष्मीबाई जैसी विरांगनाओं ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। हमारे यहां आज भी बेटी पैदा होते ही उसकी परवरिश से ज्यादा उसकी शादी की चिन्ता होने लगती है। आज महंगी होती शादियों के कारण बेटी का बाप हर समय इस बात को लेकर चिंतित नजर आता है कि उसकी बेटी की शादी की व्यवस्था कैसे होगी। समाज में व्याप्त इसी सोच के चलते कन्या भ्रूण हत्या पर रोक नहीं लग पायी है। कोख में कन्याओ को मार देने के कारण समाज में आज लड़कियों की काफी कमी होने से लिंगानुपात गड़बड़ा गया है। अगर समाज में बेटियों को उचित शिक्षा और सम्मान मिले तो बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगी। इसलिए यदि यह कहा जाय की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना नहीं हम सबकी एक जिम्मेदारी है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। यदि हम सभी एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो हम सबका यही फर्ज बनता है कि बेटियों को भी भयमुक्त वातावरण में पढ़ाएं। उन्हें इतना सशक्त बनाएं कि खुद गर्व से कह सके कि देखो वह हमारी बेटी है जो इतना बड़ा काम कर रही है।

आज लड़कियां लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। कठिन से कठिन कार्य लड़किया सफलतापूर्वक कर रही हैं। देश में हर क्षेत्र में महिला शक्ति को पूरी हिम्मत से काम करते देखा जा सकता है। लड़कियों ने अपने काम और समर्पण के दम पर कई क्षेत्रों और क्षेत्रों में खुद को साबित किया है। वे अधिक प्रतिभाशाली, आज्ञाकारी, मेहनती और परिवार और अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। लड़कियां अपने परिवार और माता-पिता के प्रति अधिक देखभाल करने वाली और प्यार करने वाली होती हैं और वे हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देती हैं। देश की अर्थव्यवस्था में भी महिलाओं का अहम योगदान है। वे श्रम शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और व्यवसायों की वृद्धि और विकास में योगदान देती हैं।

एक तरफ जहां बेटी को जन्मते ही मरने के लिये लावारिस छोड़ दिया जाता है। वहीं झुंझुनू जिले की मोहना सिंह जैसी बालिकायें भी है जो आज देश में फाइटर प्लेन उड़ा कर पूरे देश में जिले का मान बढ़ा रही हैं। समाज में सभी को मिलकर लड़का-लड़की में भेद नहीं करने व समाज के लोगों को लिंग समानता के बारे में जागरूक करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। देश में बालिकाओं के साथ हर दिन बलात्कार, प्रताड़ना की घटनायें अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। बालिकायें कहीं भी अपने को सुरक्षित नहीं समझती हैं। ऐसे माहौल में देश की बालिकायें कैसे आगे बढ़ पायेगीं। समाज के पढ़े-लिखे लोगों को आगे आकर कन्या भ्रूण हत्या जैसे घिनौने कार्य को रोकने का माहौल बनाना होगा। ऐसा करने वाले लोगों को समझा कर उनकी सोच में बदलाव लाना होगा। लोगों को इस बात का संकल्प लेना होगा कि ना तो गर्भ में कन्या की हत्या करेगें ना ही किसी को करने देगें। तभी देश में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लग पाना संभव हो पायेगा। सरकार व समाज को मिलकर ऐसे वातावरण का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिये जिसमें बालिकायें खुद को महफूज समझ सकें। समाज और राष्ट्र के विकास के लिए बालिकाओं के महत्व को स्वीकार करना और बढ़ावा देना आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि एक लड़की समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वह एक मां, एक बेटी, एक पत्नी इस तरह कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। उसे घर की शांति बनाए रखने वाली स्तंभ माना जाता है और फिर भी उसका अपमान किया जाता है। स्त्रियां ही संतति की परम्परा में मुख्य भूमिका निभाती है फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियां उपेक्षित ही रही है।

देशों के लिए भी धरती के गर्भ में समाई खनिज संपदा महत्वपूर्ण

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट से एक बात साफ हो जानी चाहिए कि आज अमेरिका ही नहीं दुनिया के अन्य देशों के लिए भी धरती के गर्भ में समाई खनिज संपदा महत्वपूर्ण हो गई है। अमेरिका चाहे यूक्रेन पर दबाव बना रहा हो या कनाड़ा को राज्य के रुप में घोषित कर अमेरिका में मिलाने की छटपटाहट हो या अन्य देशों की और भ्रकुटी तानने या मेल मिलाप के प्रयास हो सब कुछ इस खनिज संपदा को लेकर ही है। आज चाइना की मोनोपोली देखने को मिल रही है उसका बड़ा कारण भी उसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट सहित आज के बदलते युग की मांग को पूरी करने वाली पुरासंपदा के अथाह भण्डार के कारण ही है। ऐसे में वैसे तो दुनिया के देश खनि संपदा को लेकर गंभीर है वहीं हमारे देश में भी केन्द्र और राज्य सरकारें खनिज खोज, खनन और खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की कमर कस ली है। ऐसे में राजस्थान सरकार भी माइनिंग सेक्टर प्रोएक्टिव भूमिका निभाते हुए आगे आया है। वर्तमान सरकार खासतौर से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को खनन क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। राजस्थान की सरकार द्वारा योजनाबद्ध प्रयासों के तहत प्रदेश में खनिज से जुड़े सभी पहलूओं के योजनाबद्ध क्रियान्वयन, समन्वय, प्रबंधन, प्रभावी मोनेटरिंग, एक्सप्लोरेशन, राजस्व, निवेश एवं रोजगार बढ़ोतरी, सस्टेनेबल माइनिंग, माइनिंग सेक्टर में देश दुनिया में हो रहे नवाचार और नवीनतम तकनीक और उसके प्रदेश में उपयोग सहित विभिन्न बिन्दुओं को लेकर विभाग द्वारा उच्चस्तरीय परियोजना मोनेटरिंग इकाई (पीएमयू) का गठन किया है। माना जा रहा है कि प्रदेश में क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक खनिजों के साथ ही प्रधान व अप्रधान खनिजों के विपुल भण्डारों को देखते हुए पीएमयू के गठन से खनिज क्षेत्र को और अधिक गतिशील बनाया जाएगा। इससे खानें जल्दी परिचालन आने के साथ ही निवेश एवं रोजगार के अवसर बढेंगे। वैसे भी आने वाले समय में माइनिंग सेक्टर की भूमिका में बड़ा बदलाव आने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रप्रति ट्रॅप की छटपटाहट से इसे आसानी से समझा जा सकता है।

अमेरिका कभी कनाडा को अमेरिका का राज्य ही बनाने में जुटा है तो यूक्रेन की खनिज संपदा अपने नाम करवाने या रुस पर दबाव बनाने के पीछे धरती के गर्भ में समाई खनिज संपदा ही है। खनिज संपदा पर आज दुनिया के देशों की नजर है। चीन के वर्चस्व का बड़ा कारण उसका आरईई सहित खनिज संपदा पर एकाधिकार ही है और आज चीन के इस वर्चस्व को कम करने में ही जुटे हुए हैं। खैर यह विषयांतर होगा पर एक बात साफ है कि माइनिंग सेक्टर में

माइनिंग सेक्टर आज देश दुनिया में महत्वपूर्ण सेक्टर हो गया है। ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा प्रोएक्टिव रोल अपनाने की पहल निश्चित रुप से समय की मांग के अनुकूल है। केन्द्र सरकार भी गंभीर है और क्रिटिकल व स्ट्रेटेजिक खनिजों की नीलामी का काम तो केन्द्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। इसी तरह से केन्द्र सरकार ने मोनेटरिंग सिस्टम को मजबूत करने के साथ ही प्रोत्साहन के रुप में परफोरमेंस के आधार पर खानों की रेटिंग कर पुरस्कृत करने की पहल की है जिससे स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा को माहौल बना है। राजस्थान सरकार ने भी रेटिंग सिस्टम अरंभ करने की पहल की है।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व व मार्गदर्शन में तेजी से काम होने लगा है और राजथान ऑक्शन सहित रेवेन्यू अर्जन विकास दर आदि में अव्वल हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा माइनिंग सेक्टर में विपुल संभावनाओं को देखते हुए राजस्थान के माइनिंग सेक्टर को देश में अग्रणी राज्य बनाने पर जोर देते रहे हैं। नई खनिज नीति, एम-सेण्ड नीति, रिप्स में सहायता प्रावधान, एमनेस्टी योजना सहित प्रक्रिया के सरलीकरण और खनन क्षेत्र विकास के महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। पीएमयू के गठन के साथ ही खनन क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों को 7 सेक्टरों में चिन्हित किया गया है।

प्रमुख सचिव माइन्स टी रविकान्त का मानना है कि सभी क्षेत्रों में समन्वित व तेजी से विकास के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जोड़ते हुए पीएमयू का गठन किया गया है जिससे योजनाबद्ध तरीके से तेजी से आगे बढ़ा जा सके। एक्सप्लोरेशन, ऑक्शन, शीध्र परिचालन, रिसर्च एवं डव्लपमेंट, जीरो लॉस माइनिंग, इकोटूरिज्म की संभावनाओं, पेपरलेस सहित विभिन्न गतिविधियों का समावेश किया गया है। विभाग के वरिष्ठ व विशेषज्ञ अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।

खनिज क्षेत्र से जुड़े 7 प्रमुख सेक्टरों में से पहले एक्सप्लोरेशन व ऑक्शन का बनाया गया है। इस दल द्वारां कोमोडिटी, मिनरल ग्रेड, खनन के प्रकार सहित विभिन्न बिन्दुओं पर कार्य करेगी। यह दल जीएसआई सहित तकनीकी विशेषज्ञों से समन्वय बनाते हुए एक्सप्लोरेशन से ऑक्शन आदि संबंधित कार्यों को और अधिक प्रभावी गति दी जा सकेगी। इसी तरह से ऑक्शन किये गये माइनर और मिनरल ब्लॉकों को जल्द से जल्द परिचालन में लाने के लिए संबंधित स्टेक होल्डर्स व खान विभाग सहित संबंधित विभागों से समन्वय बनाते हुए आवश्यक अनुमतियां दिलाने में सहयोग के साथ ही शीघ्र परिचालन में लाने का कार्य करेगी। विभाग का जोर खनन क्षेत्र में राजस्व बढ़ाने और राजस्व में किसी भी तरह की छीजत को रोकना भी है और इसके लिए एक दल को मोनेटरिंग सहित आवश्यक सभी जिम्मेदारियां दी गई है। डीएमएफटी के कार्य को गति देने और राशि के बेहतर उपयोग की मोनेटरिंग की जिम्मेदारी सौंपते हुए डीएमएफटी फण्ड के अन्य प्रदेशों में उपयोग को लेकर अध्ययन सहित योजना, क्रियान्वयन व मोनेटरिंग का फ्रेमवर्क तैयार करने को कहा गया है। राज्य सरकार का सस्टेनेबल माइनिंग पर जोर रहने के साथ ही बदलते परिवेश में यह आवश्यक भी हो गया है। सस्टेनेबल माइनिंग और ऑटोमेशन और तकनीक सेक्टर दल द्वारा स्टार रेटिंग, बंद व कार्य नहीं कर रही खानों में इको टूरिज्म की संभावनाओं व क्रियान्वयन, डम्प ओवरवर्डन आदि के रिसाइक्लिनिंग व उपयोग, श्रेष्ठ कार्य करने वाली खानों को प्रोत्साहित करने के साथ ही विभागीय सिस्टम को नई तकनीक से जोड़ने और पेपरलेस करने की दिशा में कार्य दिया गया है। इसी तरह से खनिज क्षेत्र में शोध एवं विकास को बढ़ावा देने, अधिकारियों के रिओरियेंटेशन, खनन क्षेत्र से जुड़े स्टेक होल्डर्स व विभाग के बीच साझा मंच उपलब्ध कराने, देश दुनिया में तकनीक में आ रही बदलाव से रुबरु कराने सहित इस तरह के कार्यों के लिए कॉन्क्लेव, सेमिनार, संगोष्ठियां, प्रशिक्षण कार्यक्रम की रुपरेखा व आयोजन का कार्य किया जाएगा। राज्य सरकार ने पीएमयू गठित कर जिम्मेदारी तय करने के साथ ही सरकार की ईच्छा शक्ति स्पष्ट कर दी है। अब पीएमयू टीम को जी जान से जुटते हुए माइनिंग के सभी क्षेत्रों में अग्रणी बनाने के लिए जुट जाना होगा।

माइनिंग सेक्टर आज देश दुनिया में महत्वपूर्ण सेक्टर हो गया है। ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा प्रोएक्टिव रोल अपनाने की पहल निश्चित रुप से समय की मांग के अनुकूल है। केन्द्र सरकार भी गंभीर है और क्रिटिकल व स्ट्रेटेजिक खनिजों की नीलामी का काम तो केन्द्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। इसी तरह से केन्द्र सरकार ने मोनेटरिंग सिस्टम को मजबूत करने के साथ ही प्रोत्साहन के रुप में परफोरमेंस के आधार पर खानों की रेटिंग कर पुरस्कृत करने की पहल की है जिससे स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा को माहौल बना है। राजस्थान सरकार ने भी रेटिंग सिस्टम अरंभ करने की पहल की है।

बसपा का सियासी संदेश, सपा में 'तनाव'

उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव से लेकर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों तक की चहल-पहल दिखने लगी है। इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो बहिन मायावती ने मान्यवर कांशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए कई राजनैतिक संदेश दिए। बहिन मायावती ने अपनी जनसभा में एक ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करके राजनैतिक विश्लेषकों को हैरान किया तो दूसरी ओर अगले विधानसभा चुनावों में बिना किसी गठबंधन के उतरने की घोषणा भी कर दी है। बसपा के शक्ति प्रदर्शन को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में बसपा की बढती ताकत से समाजवादी पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। बहिन मायावती ने न केवल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की अपितु यह भी कहा कि यदि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी जुमला न साबित हुआ तो वह पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी होंगी।

बहिन मायावती अपनी 2007 की रणनीति को अपनाते हुए पुनः सामाजिक न्याय को आधार बनाकर ही चुनावी मैदान में उतरेंगी ऐसा संकेत उनकी रैली से मिलता है। उन्होंने अपनी रैली मे भीड़ जुटा कर यह संदेश दे दिया है कि उनका कोर वोटबैंक जाटव व दलित अभी भी उनके साथ है, भले ही इस समय उनके पास विधानसभा में केवल एक विधायक और मात्र 9 प्रतिशत वोट है। बहिन मायावती अपनी रैली में भाजपा के प्रति नरम व सपा तथा कांग्रेस के प्रति गरम दिखाई पड़ीं। उन्होंने अपनी रैली में कांग्रेस व सपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस संविधान पर नाटकबाजी कर रही है। कांग्रेस ने देश पर आपातकाल लगाकर बाबा साहब के बनाए संविधान का अपमान किया था। कांग्रेस ने बाबा साहब का कभी भी सम्मान नहीं किया।उन्होंने केंद्र सरकार में रहने पर उन्हें आयकर और सीबीआई की जांच में फंसाने की कोशिश की ताकि डा. आंबेडकर और कांशीराम के कारवां को रोका जा सके। अब उसी कांग्रेस के लोग संविधान की प्रति हाथ में लेकर नाटकबाजी कर रहे हैं। सपा पर तीखा हमला बोलते हुए बहिन मायावती ने कहा कि सपा की सराकर में दलितों व पिछड़ों का सर्वाधिक उत्पीड़न हुआ। उन्होंने सपा सरकार की अराजकता पर हमला किया।

बसपा रैली में बहिन मायावती के भतीजे आकाश आनंद की लॉन्चिंग के साथ-साथ मायावती के सबसे करीबी माने जाने वाले नेता सतीशचंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा की भी लॉन्चिंग हो गई है। मायावती ने उनके कामकाज की प्रशंसा भी की। जातीय समीकरण साधने के लिए सतीशचंद्र मिश्र के अलावा उमाशंकर सिंह को भी मंच पर जगह दी गई। प्रशंसनीय बात है कि इस रैली की तैयारी बहिन मायावती और उनके कार्यकर्ता बहुत ही शांत व अनुशासित तरीके से कर रहे थे। बसपा व बहिन मायावती अपने वोटर्स के मध्य बहुत समझदारी के साथ संपर्क बनाती हैं और यही कारण है कि उनका वोटबैंक काफी सीमा तक सुरक्षित रहा है; यद्यपि 2017 के बाद जाटव मतदाता में सेंध लग चुकी है जिसे फिर से भरोसा दिलाकर वापस लाना बहिनजी के लिए एक कठिन चुनौती है। लंबे समय से बहिनजी का नाम तथा आवाज केंद्रीय राजनीति से दूर रहने के कारण दलित राजनीति में चंद्रशेखर ह्लरावणह्ल जैसे लोगों का उभार हुआ है जो बसपा के परम्परागत वोटबैक पर दावा ठोंक रहे हैं।

बसपा सुप्रीमो ने भले ही जोर देकर कहा है कि आगामी चुनावों में प्रदेश में बसपा की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी जाएगी किंतु यह फिलहाल संभव नहीं प्रतीत हो रहा हें क्योकि बसपा का जो राजनैतिक समीकरण हे उस आधार पर उन्हें सत्ता प्राप्त करने के लिए कम कम के कम 30 प्रतिशत मतों की आवश्यकता होगी और वह अभी मात्र 9 प्रतिशत ही है। प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों में बसपा कार्यकताओं की धरातल पर कड़ी मेहनत के बाद यह मत प्रतिशत 15-20 पहुँच सकता है। बहिन जी ने खुले मंच से जिस प्रकार से योगी जी की प्रशंसा की वह बसपा के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है क्योंकि संभव है इससे प्रदेश का मुस्लिम मतदाता सपा गठबंधन के साथ जाना पसंद करे।

भले ही बसपा नेत्री मायावती का 2027 में अपने बलबूते पर सरकार में आने का दावा अतिशयोक्ति हो किन्तु इससे 2027 में सपा-बसपा गठबंधन की चचाओं को विराम लग गया है। साथ ही बहिन जी के दावे से सपा गठबंधन के लिए गहरा तनाव और भाजपा के लिए राहत की सूचना आ गई है।

बदलाव एवं विकास की राह खोजता बिहार चुनाव

बिहार में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। मतदान की तिथियों की घोषणा के साथ ही लोकतंत्र का यह महायज्ञ आरंभ हो चुका है, जिसमें करोड़ों मतदाता दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को अपने मत के माध्यम से राज्य की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि विचार और व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है। बिहार लंबे समय से जिस पिछड़ेपन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अराजकता की बेड़ियों में जकड़ा रहा है, उससे मुक्ति का यह अवसर है। 14 नवंबर को मतगणना के साथ बिहार में नई सरकार की तस्वीर सामने होगी, लेकिन राज्य में सियासत जिस तरह आकार ले रही है, मतदान तक कई उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। बिहार के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो यह धरती कभी बुद्ध की करुणा और चाणक्य की नीति की जननी रही है, लेकिन आज वही बिहार कानून व्यवस्था की विफलताओं, जातिवाद की जंजीरों और विकासहीनता की विवशताओं से जूझ रहा है। सड़कें टूटी हैं, शिक्षा व्यवस्था जर्जर है, चिकित्सा तंत्र कमजोर है, और रोजगार की तलाश में हर साल लाखों युवा अपनी मातृभूमि छोड़ने को विवश हैं। ऐसे में यह चुनाव एक सामाजिक जागृति का अवसर भी है, जब मतदाता केवल चेहरे नहीं, चरित्र और चिंतन को वोट देंगे।

राजनीतिक दल अपनी-अपनी घोषणाओं, वादों और दृष्टि-पत्रों के साथ मैदान में हैं। कोई ह्लनया बिहारह्ल बनाने का नारा दे रहा है, तो कोई विकसित बिहार का। लेकिन सवाल यह है कि क्या घोषणाओं से बिहार का भाग्य बदलेगा, या फिर यह चुनाव भी परंपरागत नारों और जातीय समीकरणों के हवाले हो जाएगा? यह समय है कि जनता दलों से नहीं, दिशा से जुड़ाव करे; नारे से नहीं, नैतिकता से संवाद करे। पिछले दो दशकों से नीतीश कुमार बिहार का चेहरा बने हुए हैं और यह चुनाव भी अलग होता नहीं दिख रहा। मूल सवाल यही है कि क्या नीतीश को एक और मौका जनता देगी? राज्य में एनडीए ने उन्हें आगे कर रखा है और महागठबंधन से सीधी टक्कर मिल रही है। 2005 से नीतीश कुमार बीच कें कुछ समय को छोड़ कर सत्ता पर काबिज हैं। इस दौरान उन्होंने 9 बार शपथ ली और कई बार पाला बदला। गठबंधन के साथी बदलते रहने और कम सीटों के बावजूद मुख्यमंत्री वही बने। इसके पीछे उनकी अपनी ह्यसुशासन बाबूह्ल की छवि भी है, लेकिन अब इसे चुनौती मिल रही है। पहली बार नीतीश सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरने की कोशिश हो रही है। वहीं, कानून-व्यवस्था का मामला भी चिंता बढ़ाने वाला है। हाल के महीनों में पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका और हॉस्पिटल में घुसकर गैंगस्टर की हत्या ने सरकार की परेशानी बढ़ाई। नीतीश और भाजपा ने लालू-राबड़ी यादव के कार्यकाल को हर चुनाव में जंगलराज की तरह पेश किया, पर अब सवाल विपक्षी दल पूछ रहे हैं। यह चुनाव ऐसे अनेक सवालों के घेरे में हैं।

विकास पर जोर के बावजूद बिहार की राजनीति में जाति एक निर्णायक कारक है। हर पार्टी की चुनावी रणनीति समुदाय आधारित लामबंदी से गहराई से प्रभावित है। दोनों प्रमुख गठबंधन एनडीए ओर महागबंधन सीट बंटवारे की बातचीत में उलझे हैं। 243 विधानसभा सीटों में से गठबंधन में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और किसे कोन-सी सीट मिलेगी, यह विवाद का विषय है। पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला हुआ था- इस बार समीकरण में प्रशांत किशोर की जन सुराज भी है, जो भ्रष्टाचार ओर पलायन का मुद्दा उठाए हुए हैं। कुछ और भी नये राजनीतिक दल मैदान में हैं। बिहार की सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुदृढ़ता की है। आए दिन होने वाली अपराध घटनाएं और अराजकता ने राज्य की छवि को धूमिल किया है। एक ऐसा शासन चाहिए जो भयमुक्त समाज दे सके, जहां नागरिक सुरक्षित

विकास पर जोर के बावजूद बिहार की राजनीति में जाति एक निर्णायक कारक है। हर पार्टी की चुनावी रणनीति समुदाय आधारित लामबंदी से गहराई से प्रभावित है। दोनों प्रमुख गठबंधन एनडीए ओर महागबंधन सीट बंटवारे की बातचीत में उलझे हैं।

महसूस करें, जहां अपराध पर अंकुश हो और न्याय त्वरित मिले। विकास तभी संभव है जब विश्वास का माहौल बने।

बिहार की राजनीति में इस बार कई नए दल और कई पुराने चेहरे नए दल के साथ दिखाई देने वाले हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी ह्यजनसुराजह्ल, तेजप्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पहली बार बिहार विधानसभा के चुनाव में नजर आने वाली है। ऐसे में सभी दल चुनावी जंग में ताल ठोकने को तैयार है। मगर देखने वाली बात ये होगी कि कौन सी पार्टी अपना कितना दम दिखा पाती है? क्या प्रशांत किशोर की पार्टी उनके दावे के अनुसार प्रदर्शन करती है या फुस्स साबित होती है, वहीं, तेजप्रताप यादव अपनी पार्टी बनाकर तेजस्वी यादव को कितना झटका देते है। यह सब अब चुनाव के परिणाम पर तय होगा। साथ ही यह भी तय होगा कि कौन सी पार्टी अपना अस्तित्व बचा पाती है कौन नहीं? यह चुनाव बिहार की आत्मा को झकझोरने वाला क्षण है।

यहां की जनता अब सिर्फ रोटी-कपड़ा-मकान नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, और सम्मानजनक जीवन चाहती है। यह चुनाव इस आकांक्षा का प्रतीक है। जो भी दल इस वास्तविकता को समझेगा, वही बिहार का भविष्य गढ़ पाएगा।

आज बिहार के मतदाता अधिक सजग एवं विवेकशील हैं। वे जानते हैं कि सत्ता परिवर्तन से अधिक जरूरी है संस्कृति परिवर्तन, राजनीतिक शुचिता और प्रशासनिक जवाबदेही। यह चुनाव केवल विधानसभा की सीटें तय नहीं करेगा, बल्कि यह तय करेगा कि क्या बिहार अपनी पुरानी परछाइयों से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ पाएगा। क्योंकि बिहार में पिछड़ेपन, भ्रष्टाचार, अराजकता की चर्चा होती रहती है, इसलिये यह स्वाभाविक है कि राज्य का विकास, कानून व्यवस्था एवं रोजगार का मुद्दा भी पक्ष-विपक्ष के बीच एक प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा। हालांकि पिछली सरकारों के दौर में बिहार बदहाली के दौर से काफी निकल चुका है और विगत दो दशक में यहां की स्थितियां काफी बदली है। इस बार बिहार चुनाव बदला-बदला होगा, इसकी आहट उन घोषणाओं से भी मिलती है, जो नीतीश सरकार ने की हैं। महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए पहली बार इस पैमाने पर ऐलान किए गए हैं। वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने पूछा है कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा? जनता वादों पर भरोसा करती है या बदलाव संग जाती है, जवाब मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।

वैसे, बिहार चुनाव का इतना ज्यादा महत्व कोई नई बात नहीं है। विगत दो दशक से एक विशेष क्रम बना हुआ है। लोकसभा चुनाव के अगले साल बिहार विधानसभा के चुनाव होते हैं। केंद्र में जो पार्टी विपक्षी गठबंधन में रहती है, वह बिहार विधानसभा चुनाव में अपना पूरा जोर लगा देती है, जिससे चुनाव कुछ ज्यादा रोचक एवं उत्तेजक बन जाता है। सियासी स्थिति का आकलन करें, तो बिहार में लगभग बीस साल शासन के बावजूद जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार की ताकत को कोई भी खारिज नहीं कर रहा है। भाजपा पूरी मजबूती से नीतीश कुमार के साथ खड़ी है, ताकि सत्ता बनी रहे। दूसरी ओर, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाला महागठबंधन अभी नहीं, तो कभी नहीं वाले अंदाज में जोर लगा रहा है। लोकतंत्र की इस परीक्षा में बिहार एक नई इबारत लिख सकता है-एक ऐसा बिहार जो शिक्षित हो, संगठित हो, और सजग हो। जहां राजनीति सेवा का माध्यम बने, संघर्ष का नहीं; जहां सत्ता संवेदना की भाषा बोले, स्वार्थ की नहीं। बिहार का यह जनादेश वास्तव में इतिहास रच सकता है-यदि जनता जाति नहीं, न्याय को चुने; वादा नहीं, विश्वास को चुने। यह चुनाव बिहार के भाग्य परिवर्तन की कुंजी बन सकता है-बशर्ते हम सब मिलकर कहें- अब की बार, सुशासन और सुधार।

घूँघट की बगावत

12 अक्टूबर 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

जब जाति इस गुटबाजी का हिस्सा बन जाती है, तो योग्यता, ईमानदारी और संवेदनशीलता, सब हाशिए पर चले जाते हैं। पूरन कुमार की मौत झूठी प्रतिष्ठा के इस तंत्र पर एक नैतिक छाया डालती है। यह घटना सिर्फ.आत्महत्या नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की आत्मा की हत्या है, जो अपने अधिकारियों को मानसिक और नस्लीय रूप से इतना भ्रष्ट कर देती है कि वे जीवन त्यागने पर मजबूर हो जाते हैं। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की आत्महत्या ने प्रशासनिक जगत को स्तब्ध कर दिया। अपने सुसाइड नोट में, उन्होंने 15 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को अपना निशाना बताया है और कहा है कि वे जाति-आधारित अपमान कर रहे हैं और मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने डीजीपी शत्रुघ्न कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया सहित कुल 14 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर संख्या 156 दर्ज की। हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार है कि इतने सारे वरिष्ठ कर्मचारियों पर एससी/एसटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत एक ही सजा सुनाई गई है। लेकिन एक पल में हमें एहसास हुआ कि यह नौकरशाही में दबे जातिगत भेदभाव पर एक बड़ा प्रहार था।

जाति, ईर्ष्या और जीवन: नौकरशाही का स्याह पहलू

7 अक्टूबर को हरियाणा की प्रशासनिक मशीनरी में एक ऐसी गूंज उठी जिसने नौकरशाही की शालीनता की पोल खोल दी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार ने चंडीगढ़ सेक्टर 11 स्थित अपने सरकारी आवास पर खुद को गोली मार ली। लेकिन यह आत्महत्या नहीं थी; यह जातिगत भेदभाव, उस सीढ़ी पर चढ़ने के संघर्ष और इसी व्यवस्था में अंतर्निहित उत्पीड़न की आत्महत्या थी। अब, चंडीगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और उसकी खामोशी कानून की दस्तक बन गई है। एफआईआर संख्या 156, जिसमें बाद में डीजीपी शत्रुघ्न कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को आरोपी बनाया गया, और 14 अन्य को आदेश पर अधिकारी बनाया गया, भारत के प्रशासनिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 108, 3(5) और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के तहत दर्ज होने के कारण, यह मामला इस बात का प्रमाण है कि सत्ता के ऊँचे पदों पर आज भी जातिवाद उतनी ही जोर-शोर से घूमता है जितना कि गाँवों की गलियों में।

पूरन कुमार के सुसाइड नोट में 15 आईएएस और आईपीएस अफसरों के नाम हैं। हर नाम एक आरोप है, और हर आरोप एक आरोपः क्या इस देश में संवैधानिक शक्तियों वाला कोई भी अधिकारी अपनी जाति की बेड़ियाँ नहीं तोड़ सकता? उन्होंने कहा, ₹आप एक ₹अतिरिक्त पदर थे, और उनके कौशल को हमेशा दबा दिया गया, और जातिगत धमकियों के साथ-साथ गालियों ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया।₹ पूरन कुमार का करियर रिकॉर्ड इस निष्कर्ष की पुष्टि करता है। पुलिस सेवा में वे कठोर और सच्चे थे, लेकिन उन्हें बार-बार निचले पदों पर स्थानांतरित किया गया—अब आईजी होमगार्ड, फिर आईजी दूरसंचार। जब उन्हें अप्रैल 2023 में रोहतक रेंज के आईजी का पद मिला, तो उन्हें लगा होगा कि उनकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन पाँच महीने बाद ही उनका तबादला सुनारिया पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में कर दिया गया—और यहीं से उनका मानसिक पतन शुरू हुआ। यह कहानी एक अधिकारी की नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की है जो ₹योग्यता₹ से ज्यादा ₹पहचान₹ को महत्व देती है। आरक्षण इस देश में एक नया भविष्य तो लाता है, लेकिन व्यवस्था उसे मान्यता देने से इनकार करती है।

दलित अधिकारियों को अक्सर कमतर आंका जाता है; उन्हें ₹योग्य अधिकारी₹ की बजाय ₹आरक्षण अधिकारी₹ कहा जाता है। पूरन कुमार की मौत ने साबित कर दिया कि जाति न केवल समाज में, बल्कि सत्ता के गलियारों में भी व्याप्त है। पूरन कुमार की पत्नी, आईएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार ने दो अलग-अलग याचिकाएँ दायर कीं—एक में केवल डीजीपी और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की माँग की गई है, और दूसरी में सभी 15 अधिकारियों की गिरफ़्तारी की माँग की गई है। यह किसी एक अधिकारी की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील पत्नी और सहकर्मी की लड़ाई है जो राज्य से अपने लिए न्याय चाहती है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ.आत्महत्या नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। कई आईएएस, आईपीएस और एचसीएस अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज होने के बाद अनुसूचित जाति समुदाय के पूरन परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त की है। यह अभूतपूर्व है, नौकरशाही में आमतौर पर चुप्पी की संस्कृति व्याप्त रहती है, जहाँ अधिकारी अक्सर अपने साथियों के बारे में बात करने से भी बचते हैं। लेकिन इस बार यह चुप्पी टूट गई है। अधिकारी इस समय कह रहे हैं कि पूरन कुमार की हत्या कोई व्यक्तिगत हत्या नहीं है—वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके विचार समानता और सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा रखते थे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने परिवार से मुलाकात की और उन्हें निष्पक्ष जाँच का आश्वासन दिया। लेकिन क्या यह वादा न्याय में तब्दील होता है? क्या राज्य सरकार इतनी हिम्मत जुटा पाएगी कि एक वरिष्ठ अधिकारी को डीजीपी पद से हटाकर पुलिस अधीक्षक को पद से हटा दे? या यह भी किसी अन्य ₹आंतरिक जाँच₹ की तरह फाइलों में सिमट कर रह जाएगा? हरियाणा की नौकरशाही में वर्षों से जाति-आधारित गुटबाजी के बारे में चर्चा होती रही है जो अधिकारियों की नियुक्तियों, तबादलों और पदोन्नति को प्रभावित करती है। यह ₹कौन किसका है₹ का मामला है, और पद से ज्यादा वरीयता हासिल करनी होती है। और जब जाति इस गुटबाजी का हिस्सा बन जाती है, तो योग्यता, ईमानदारी और संवेदनशीलता, सब हाशिए पर चले जाते हैं। पूरन कुमार की मौत झूठी प्रतिष्ठा के इस तंत्र पर एक नैतिक छाया डालती है। यह घटना सिर्फ.आत्महत्या नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की आत्मा की हत्या है, जो अपने अधिकारियों को मानसिक और नस्लीय रूप से इतना भ्रष्ट कर देती है कि वे जीवन त्यागने पर मजबूर हो जाते हैं।

इस मामले के बाद, नौकरशाही में जातिगत भेदभाव पर किसी तरह का खुला संवाद उभर सकता है। लेकिन यह भी डर है कि यह मामला प्रशासनिक औपचारिकता बनकर रह जाएगा—जैसा कि हमेशा होता आया है। एक जाँच समिति बिठाई जाएगी, बयान दर्ज किए जाएँगे, और एक निर्णायक रिपोर्ट में इसे ₹निजी कारणों से आत्महत्या₹ घोषित कर दिया जाएगा। महान पूरन कुमार का लिखा एक-एक शब्द आज भी एक सवाल की तरह हवा में तैर रहा है: ₹जब न्याय करने वाले ही अन्याय करने लगें, तो विरोध कौन करे?₹₹ यह उन अनेक उदाहरणों में से अंतिम है जब एक सहानुभूतिशील अधिकारी ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह दर्शाया कि जातिवाद की पीड़ा को सत्ता के शिखर से कम नहीं किया जा सकता। हालाँकि, यह अहसास कि जाति ने आज भारत की राजनीति को संक्रमित कर दिया है, न केवल सरकार की, बल्कि समाज की भी ज़िम्मेदारी है। पूरन कुमार चले गए हैं, लेकिन उनके सुसाइड नोट से यह स्पष्ट है कि नौकरशाही की चुप्पी भी एक आपराधिक कृत्य है। उनकी मृत्यु के लिए व्यवस्था को न केवल अपराधियों, बल्कि अपनी सोच को भी जवाबदेह ठहराना होगा। क्योंकि जब तक यह व्यवस्था नहीं बदलती, तब तक हर पूरन कुमार के लिए यह हमेशा एक गोली की तरह रहेगी।

डॉ. सत्यवान सौरभ

करवा चौथ: परंपरा, प्रेम और पितृसत्ता के बीच

हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी को जब शाम का सूरज डूबता है, तो भारत के कोने-कोने में सजी-संवरी महिलाएं थाली में दीप, छलनी और करवा सजाकर चाँद के दर्शन करती हैं। उनके माथे पर लाल बिंदी, हाथों में मेंहदी, आँखों में इंतजार और होठों पर एक ही सवाल—ह्लचाँद निकला क्या? यह दृश्य भारतीय संस्कृति की सुंदरता का प्रतीक भी है और उसकी गहराई में छिपे सामाजिक अर्थों का आईना भी। करवा चौथ का व्रत उत्तर भारत में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएँ अपने पति की दीर्घायु के लिए सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं। परंपरा के अनुसार यह व्रत सुहाग की स्थिरता और पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, और दिनभर की तपस्या के बाद जब चाँद निकलता है तो पत्नी छलनी से पति का चेहरा देख कर व्रत तोड़ती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह व्रत सिर्फ प्रेम और आस्था की अभिव्यक्ति है या समाज की पितृसत्तात्मक जड़ों में गहरे धंसा एक प्रतीक? भारतीय समाज में स्त्री के जीवन को ह्लसुहागह्व से जोड़ा गया है—उसकी खुशी, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी पहचान तक। विवाह के बाद उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि उसका पति माना गया, और उसकी मृत्यु को अभिशाप समझा गया। ऐसे में करवा चौथ जैसे व्रत स्त्री के समर्पण, त्याग और सहनशीलता का उत्सव बन गए। लेकिन क्या यह प्रेम का उत्सव है या स्त्री के अस्तित्व को पति की उम्र के साथ बाँध देने का सांस्कृतिक औचित्य? आज की पढ़ी-लिखी स्त्री जब करवा चौथ का व्रत रखती है, तो उसके कारण परंपरागत नहीं भी हो सकते। कई महिलाओं के लिए यह पति के प्रति प्रेम का, साथ निभाने का, रिश्ते में सामंजस्य का प्रतीक बन चुका है। वहीं कई पुरुष भी अब पत्नी के साथ समान भाव से व्रत रखने लगे हैं—यह बदलाव सकारात्मक है। परंतु यह भी उतना ही सच है कि करवा चौथ आज एक 'कल्चरल इवेंट' बन गया है—टीवी धारावाहिकों, फिल्मों और सोशल मीडिया पर यह व्रत जितना 'ग्लैमरस' दिखाया जाता है, उतनी ही गहराई में उसका मूल अर्थ खोता जा रहा है। कभी यह व्रत गाँव की औरतों के बीच अपनापन और सहयोग का प्रतीक था। महिलाएँ एक-दूसरे के घर जातीं, मिट्टी के करवे (घड़े) में जल भरतीं, गीत गातीं—ह्लकरवा चौथ का व्रत है भाई, करवा लाना भूली न जाई ह्व यह त्यौहार उनके लिए आपसी मिलन का अवसर था, जहाँ वे जीवन की तकलीफों को साझा करतीं। पर अब यह व्रत सोने के करवे, महंगे साज-श्रृंगार और डिजाइनर साड़ियों का प्रदर्शन बन गया है। उपवास के बजाय अब ह्लइंस्टा रील्सह्व का युग है—जहाँ सजना-संवरना ही मुख्य उद्देश्य बन गया है। फिर भी, परंपराओं को केवल अंधविश्वास कहकर नकार देना भी उचित नहीं। हर संस्कृति की अपनी आत्मा होती है। करवा चौथ के पीछे जो भाव है—प्रेम, समर्पण और आस्था का—उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम परंपरा को आधुनिक दृष्टि से देखें। आज जब हम समानता, स्वतंत्रता और पारस्परिक सम्मान की बात करते हैं, तो यह व्रत भी एकतरफा नहीं रहना चाहिए। यदि पत्नी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, तो पति भी पत्नी की सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए समान भाव से प्रार्थना करे—यही सच्चा प्रेम और समानता है। दिलचस्प बात यह है कि करवा चौथ का धार्मिक या पौराणिक आधार उतना स्पष्ट नहीं है जितना कि इसके लोकप्रचलन का प्रभाव। करवा यानी मिट्टी का घड़ा, जो प्राचीन भारत में जल का प्रतीक था, और चौथ यानी चतुर्थी का दिन।

दीपावली: प्रकाशों और जीवन के गहरे पाठ

विजय गर्ग

दिवाली, या दीपावली, रोशनी, पटाखे और मिठाई का एक शानदार त्योहार से कहीं अधिक है; यह एक गहरा उत्सव है जो मानवता के कुछ सबसे अस्थायी और आवश्यक जीवन पाठों को समेटता है। गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कथाओं में जड़ रखने वाला यह पांच दिवसीय त्यौहार आत्मनिरीक्षण, नवीनीकरण और सार्वभौमिक मूल्यों की पुष्टि के लिए एक वार्षिक आह्वान है।

प्रकाशों के त्योहार से सबसे उज्ज्वल सबक यहां दिए गए हैं

1। अंधकार पर प्रकाश की विजय (बुरे पर अच्छा)

दीपावली अपने मूल में अंधेरे पर प्रकाश की विजय, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर भलाई का शक्तिशाली प्रतीक है।

आध्यात्मिक विजय: दिवाली से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध किंवदंती यह है कि भगवान राम रावण को पराजित करने के बाद अयोध्या लौट आए। अयोध्या के लोगों द्वारा उनके मार्ग को उजागर करने के लिए दीया (तेल की लैंप) जलाए जाने से अंधेरा दूर हो जाता है और धर्म की विजय होती है।

आंतरिक प्रकाश: यह विजय केवल बाहरी नहीं बल्कि व्यक्तिगत है। हर घर में जो अनगिनत दीपक जलाए जाते हैं, वे अपने आंतरिक राक्षसों पर विजय पाने के लिए एक अनुस्मारक होते हैं - जैसे अहंकार, लालच और भय - तथा आंतरिक ज्ञान और भलाई की रोशनी चमकने दें। यह उत्सव अज्ञानता के अंधेरे पर विजय पाने के लिए ज्ञान की निरंतर खोज को प्रोत्साहित करता है।

नई शुरूआत और नवीनीकरण की शक्ति

दिवाली को अक्सर वर्ष के लिए ₹पुनर्सेट बटन₹ दबाकर भौतिक और आध्यात्मिक सफाई का अवसर दिया जाता है।

सफाई और तैयारी: त्योहार से पहले पुरानी या अवांछित वस्तुओं (सफाई) को गहराई से साफ करने और फेंकने की परंपरा अतीत को साफ करने, नकारात्मक विचारों को छोड़ने और सकारात्मक नई शुरूआत का स्वागत करने के लिए तैयार होने का प्रतीक है। एक स्वच्छ स्लेट: जैसे-जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यवसाय दिवाली के साथ नया वित्तीय वर्ष मनाते हैं, त्यौहार नई शुरूआत को प्रेरित करता है। यह हमें पिछली गलतियों को दूर करने, हर चुनौती से आशावादी तरीके से निपटने और खुले दिल के साथ नए सीखने के अनुभवों को अपनाने सिखाता है।

परिवार, एकता और देने का महत्व

दिवाली एक ऐसा समय है जो समुदाय, पारिवारिक बंधन और निस्वार्थ योगदान के महत्व पर जोर देता है। एकजुटता और सामंजस्य: बहुदिवसीय उत्सव अनुष्ठानों, त्यौहारों और उपहार विनिमय के लिए परिवारों और समुदायों को एक साथ लाता है। यह एकता, वफादारी और बिना शर्त प्रेम के मूल्य को मजबूत करता है, जैसा कि उनके निर्वासन के दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के बीच गहरे बंधन से दर्शाया गया था।

देने का आनंद (दान): मिठाई साझा करने, उपहार आदान-प्रदान करने और देवी लक्ष्मी (समृद्धि की देवता) को प्रार्थना करने की परंपरा उदारता और कृतज्ञता की भावना पर प्रकाश डालती है। यह हमें याद दिलाता है कि वास्तविक धन केवल जमा होने के बारे में नहीं है बल्कि दूसरों, विशेष रूप से कम भाग्यशाली लोगों के साथ अपना समय, समर्थन और दयालुता साझा करने के बारे में भी है।

अखंडता, कर्तव्य और नैतिक नेतृत्व

दिवाली से जुड़ी कहानियां, विशेष रूप से रामायण नैतिक व्यवहार और नेतृत्व के बारे में शक्तिशाली सबक प्रदान करती हैं। एक के वचन का सम्मान करना: भगवान राम की अपने पिता के वचन पर अटल प्रतिबद्धता, भले ही इसका मतलब था कि वह अपनी हकदार सिंहासन को त्याग दे और 14 वर्षों तक निर्वासन का सामना कर ले, ईमानदारी का गहन महत्व सिखाती है, अपना वादा निभाती है तथा धर्म (धार्मिक कर्तव्य) को व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर रखती है।

नैतिक आचरण: कथा इस बात पर जोर देती है कि भले ही यह अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन एकमात्र ऐसा मार्ग है जो सच्ची और स्थायी जीत का नेतृत्व करता है। मूलतः दीपावली स्वयं जीवन का एक सुन्दर रूपण है। दीया को जलाकर, कोई केवल घर के एक कोने को उजागर नहीं करता है; वह अपनी आंतरिक रोशनी से अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने की शपथ लेता है, बुराई पर भलाई चुनता है, नवीनीकरण का स्वागत करता है और करुणा और एकता में समृद्ध जीवन जीता है। दीपावली का शाश्वत सबक यह है कि ₹आप दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं, वह बनें₹ और हमेशा अपने अंदर की रोशनी को पोषित करें ताकि वह हमारे आस-पास की दुनिया को उजागर कर सके।

पीडीए गठबंधन के लिए बसपा बनी सबसे बड़ा रोढ़ा

उप्र में मायावती की राजनीति नें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को चारों खाने चित्त कर दिया है। कभी भाजपा के लिए चुनौती नहीं रही मायावती अब सपा पर पुनः खुलकर हमलावर है। यह वहीं मायावती है जिनके सामने भरे मंच पर उनके पैरों में गिरकर सपा सुप्रीमों नें महागठबंधन की भीख मांगी थी। कभी चूहें बिल्ली का संबंध रखने वाली सपा गेस्ट हाउस कांड के बाद बसपा को फूटी आँख नहीं सुहाती थी तो मायावती नें ठान लिया था एक दिन भरे मंच से सपा की वो बेइज्जती करेंगी की सपाई हमेशा तिलमिलाते नजर आएंगे। और फिर एक दिन अखिलेश यादव भरे मंच से सपा का अहंकार मायावती के पैरों में डालकर, उनके चरण छुकर ये बता दिया था की आदर्श मान सम्मान कुछ नहीं,उनके लिए बस कुर्सी और सत्ता महत्वपूर्ण है किन्तु उसी के बाद से सपा की ऐसी दुर्गति हुई की अब मायावती को ना निगल पा रहें ना उगल पा रहा पीडीए गठबंधन वाले। इस बार उन्होंने सपा और कांग्रेस की आलोचना के साथ भाजपा शासन की तारीफ कर दी है और योगी सरकार का आभार भी जता दिया। 'आई लव मुहम्मद' के बवाल पर मायावती खुलकर सनातन के पक्ष में खड़ी हो गई। उन्होंने सपा की आलोचना की , उन्होंने केवल यह कहा कि जनहित के मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय, कुछ शरारती और स्वार्थी तत्व धर्म, देवी-देवता और खुदा के नाम पर विवाद और हिंसा पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इन मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए और सभी को भारतीय संविधान और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। इसी तरह कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि कांग्रेस वाले संविधान हाथ में रखकर नाटकबाजी करते हैं जबकि इमरजेंसी के दौरान ही संविधान पर हमला हुआ था। बहरहाल, मायावती ने दावा किया कि 2027 में उप्र में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से

बसपा की सरकार बनेगी। उन्होंने पार्टी नेता आकाश आनंद की तारीफ करते हुए कहा कि आकाश बसपा का जनाधार बढ़ाने के लिए मेरे दिशानिर्देशन में लगातार प्रयास कर रहे हैं । जब 9 अक्टूबर गुरुवार को लखनऊ में हुई महारैली में बड़ी भीड़ जुटी मौका था कांशीराम की पुण्यतिथि का जिसमें मायावती ने ये महारैली बुलाई थी , जिसका असली मकसद 2027 के चुनावों की तैयारी थी और इसके अलावा अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से सार्वजनिक तौर पर उत्तराधिकारी बताना था। उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की मुखिया मायावती ने गुरुवार को महागठबंधन की पोल खोल कर रख दी। गौरतलब है कि मायावती के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वे भाजपा की बी टीम के तौर पर काम करती रही हैं। अर्थात सीधे-सीधे न सही लेकिन चुनावों में वे इस तरह पांसे बिछाती हैं, जिससे भाजपा को फायदा हो, और सपा, कांग्रेस या अन्य भाजपा विरोधी दलों को नुकसान। जबकि जिस दलित पृष्ठभूमि से मायावती आती हैं उसी दलित राजनीति के बूते सपा भी सत्ता तक पहुंची है , उस दलित समुदाय की सबसे घोर उपेक्षा सपा के शासनकाल में हुई है, इसकी गवाही दलित उत्पीड़न के आंकड़े भी देते हैं। जब भी दलित को प्रताड़ित करने की कोई बड़ी घटना होती है, तो बहनजी से स्वाभाविक तौर पर उम्मीद की जाती है कि वे कोई बयान देंगी।

पिछले 13 सालों से मायावती सत्ता से बाहर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में दलितों का यकीन उन पर अब भी बना हुआ है, ऐसा तब लगता है जब यूपी में किसी भी चुनाव के वक़्त सपाई नेता और कई पूर्व मंत्री पीडीए के नाम पर दलितों के घर खाना खाते हुए तस्वीरें खिंचाते हैं, लेकिन जिन चमकते बर्तनों में वे भोजन करते हैं और जितने तरह के व्यंजन परोसे हुए होते हैं, उसे देखकर समझ आता है कि ये सारा तामझाम कुछ घंटों के वीडियो और तस्वीरें केवल दलितों और पिछडो को उल्लू बनाने का है असली मकसद लाल आतंक मचाने और परिवारवाद लाने का है । जिसमें सब कुछ नाटकीय है, वास्तविक नहीं। अगर दलितों को यादव तबका अपने बराबर की सामाजिक स्वीकार्यता पहले ही देता तो फिर इस तरह किसी को किसी के घर भोजन करने का ड्रामा नहीं करना पड़ता पीडीए के नाम पर । भाजपा सरकार में दलितों का जो सम्मान हुआ और जिस प्रकार कद बढ़ा है उससे चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव घबराये हुए है ऊपर से मायावती का योगी शासन की तारिफ नें पूरे पीडीए राजनीति की हवा बिगाड़ कर रख दी है। बाबा साहेब अंबेडकर से नफरत का जो इतिहास सपा का रहा है और संविधान को खत्म करने की जो कोशिशें कांग्रेस की रही है उसे जनता जान कर लगातार मोदी योगी के साथ चल रही हैं, उन पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पुरजोर तरीके से केवल धर्म विशेष के लिए आवाज उठा रहे हैं । लेकिन मायावती ने गुरुवार को योगी सरकार की तारीफ की तो वहीं सपा पर जमकर हमला बोला। जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि क्योंकि ह्यउनकीह्व अंदरूनी सांठगांठ है जारी, इसीलिए वो हैं जुल्म करने वालों के आभारी है । बता दें कि मायावती ने रैली की शुरूआत में कहा कि अभी मैंने सुना कि अखिलेश यादव ने सत्ता में आने पर कांशीराम का स्मारक बनाने की बात कही लेकिन जब सत्ता में थे तो कभी ऐसा नहीं किया। ये लोग जब सत्ता में नहीं होते हैं तो इन्हें बसपा के नेता और दलित समाज के संतों की याद आती है जब सत्ता में आते हैं तो कुछ नहीं याद रहता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बसपा की सरकार रहते हुए मैंने जिन स्मारकों का नाम कांशीराम जी के नाम पर रखा उन्हें सपा की सरकार आने पर बदल दिया गया। मायावती ने कहा कि बसपा सरकार में कांशीराम के सम्मान में स्मारक स्थल बनाया गया था। उन्होंने योगी सरकार का भी आभार जताया और कहा कि स्मारक के देखने आने वालों की टिकट से आया पैसा इस सरकार ने सपा की सरकार की तरह टिकट का पैसा दबाकर नहीं रखा। भाजपा सरकार ने ऐसा नहीं किया बल्कि स्मारक के रखरखाव के लिए खर्च किया।

पंकज सीबी मिश्रा
जौनपुर यूपी

किराये का घर ही नहीं

किराये का घर ही नहीं,
छूटा-छूटा है बहुत कुछ –
लोग, कोने, बच्चे, पेड़,
पार्क की बेंच पर बची हँसी,
खिड़की से झाँकती दोपहरें,
सब किसी पुराने पते पर रह गए।

दीवारों पर उभर आई थीं उँगलियों की छाप,
सपनों की धूल में लिपटी तस्वीरें,
रसोई के कोने में रोटियों की गर्म यादें,
अब सब किसी और की साँसों में बस गईं।

हर बार घर बदलने के साथ,
थोड़ा-थोड़ा हम भी बदल जाते हैं –
कुछ रिश्ते डिब्बों में पैक रह जाते हैं,
कुछ मुस्कुराहटें रास्ते में गिर पड़ती हैं।

कभी सोचता हूँ –
क्या इंसान सच में बसता है किसी घर में?
या घर बसता है उसके भीतर,
जहाँ भी जाए, वही किरायेदार बनकर।

डॉ. सत्यवान सौरभ

घूँघट की बगावत

12 अक्टूबर 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

6

बाजार के जहरीले आईने : जब लोग उपभोक्ता बन जाते हैं, इंसान नहीं

आज का समाज उपभोक्ता संस्कृति का गुलाम बन चुका है। लोग जरूरत के लिए नहीं, बल्कि दिखावे के लिए चीजें खरीद रहे हैं। मोबाइल फोन से लेकर कपड़ों तक, हर वस्तु अब पहचान और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई है। ह्लोग क्या कहेंगेह्व के डर में लोग कर्ज में डूबते जा रहे हैं। असली जरूरतें पीछे छूटती जा रही हैं और कृत्रिम इच्छाएं आगे बढ़ रही हैं। उपभोक्तावाद का यह जाल धीरे-धीरे इंसान की आत्मा को खाली कर रहा है।

हमारा समाज आज विकास की तेज रफ़्तार पर तो है, पर दिशा कहीं खो चुका है। पहले इंसान जरूरतों के लिए चीजें खरीदता था, अब चीजें इंसान को खरीद रही हैं। अब बाजार केवल सामान नहीं बेचता, वह हमारी पहचान बेचता है। यह हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हम कौन हैं, हमारी औकात क्या है, और हमारी असली कीमत कितनी है। आज हर तरफ एक अजीब सी होड़ है – दिखावे की, ब्रांड की, और झूठे रुतबे की। लोग अब ज़िंदगी नहीं जी रहे, वे उसे प्रदर्शित कर रहे हैं। हर तस्वीर, हर पोस्ट, हर कपड़े और हर मोबाइल के पीछे एक ही सवाल छिपा होता है झ ह्लोग क्या कहेंगे?

उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म ने हमारे समाज की नसों में जहर की तरह जगह बना ली है। पहले व्यक्ति वस्तु का उपयोग करता था, अब वस्तुएँ व्यक्ति का उपयोग कर रही हैं। ब्रांड अब हमारी जरूरतों के नहीं, बल्कि हमारी असुरक्षाओं के सौदागर बन गए हैं। वे हमें यह यकीन दिला चुके हैं कि जब तक हमारे पास महंगा मोबाइल, बड़ा घर और इंस्टाग्राम पर दिखाने लायक जीवन नहीं है, तब तक हम अधूरे हैं।

कभी कहा गया था कि मनुष्य वस्तु का मालिक है, पर अब वस्तुएँ मनुष्य के मन और मानसिकता की मालिक बन चुकी हैं। ऐप्पल का मोबाइल हो या महंगी कार, इनका उद्देश्य सुविधा नहीं, प्रतिष्ठा बन चुका है। लोग अब पर्दा इसलिए नहीं हटाते कि उन्हें हवा लगे, बल्कि इसलिए हटाते हैं कि तस्वीर अच्छी आए। इज्जत अब चरित्र में नहीं, कैमरे की फ्रेम में दिखती है।

सोशल मीडिया इस उपभोक्ता संस्कृति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। पहले लोग बातें करते थे, अब पोस्ट करते हैं। पहले खुशी आती थी, अब उसे रील में एडिट किया जाता है। पहले त्यौहार मनाए जाते थे, अब दिखाए जाते हैं। हर लाइक आत्मविश्वास का मापदंड बन गया है, और हर टिप्पणी आत्म-मूल्य का प्रमाण। हम खुद से कम और दूसरों की निगाह से ज्यादा जीने लगे हैं। कपड़े ब्रांडेड हैं, पर सोच उधार की है; चेहरे चमकते हैं, पर दिल थके हुए हैं।

एक समय था जब गाँव की औरतें पर्दे में रहकर भी मर्यादा और सम्मान की मिसाल होती थीं। आज वही परंपरा इंस्टाग्राम की चमक में खो गई है। अब पर्दा शर्म या संकोच का नहीं, बल्कि फोटोशूट का हिस्सा बन गया है। लोग कहते हैं – ह्लहम तो आधुनिक हैं ह्व पर यह आधुनिकता नहीं, मानसिक गुलामी है – जहाँ दिखावा आत्म-सम्मान पर भारी पड़ता है।

सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपनी मासिक कमाई का बड़ा हिस्सा केवल इसीलिए ईएमआई में खर्च कर देता है ताकि लोग कह सकें कि उसके पास ह्यआइफोनह्व है – तो वह उपभोक्ता नहीं, बल्कि उपभोग का शिकार बन चुका है। फोन वही काम करता है – बात करना, संदेश भेजना, संपर्क बनाए रखना – पर हमारे दिमाग ने उसे सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बना लिया है।

बाजार हमें यह नहीं बताता कि हमें क्या चाहिए, बल्कि यह तय करता है कि हमें क्या चाहना चाहिए। विज्ञापन इतने मनोवैज्ञानिक हो चुके हैं कि वे पहले हमारे भीतर कमी का एहसास जगाते हैं, फिर उसी कमी का समाधान बेचते हैं। यह एक मानसिक व्यापार है – पहले असंतोष पैदा करो, फिर संतोष बेचो। मोबाइल कंपनियाँ कहती हैं – ह्लहमारा फोन आपकी पहचान है ह्व धीरे-धीरे यही सोच हमारी आत्मा तक उतर गई है। हमारी पहचान, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान – सब अब ब्रांड वैल्यू में बदल चुके हैं।

जब मूल्य वस्तु में बदल जाते हैं, तो रिश्ते भी सौदे में बदल जाते हैं। आज लोग उपहार नहीं, ब्रांडेड चीजें देते हैं। शादी अब संस्कार नहीं, सामाजिक प्रदर्शन बन गई है। त्योहार अब भावना नहीं, फोटो सेशन बन चुके हैं। यह सब मिलकर हमारी संवेदनाओं को खोखला और नकली बना रहे हैं।

पहले माता-पिता बच्चों को सिखाते थे –कपड़े से नहीं, कर्म से पहचान होती है ह्व अब बच्चे कहते हैं – ह्लमाँ, वही ब्रांड चाहिए जो मेरे दोस्त के पास है ह्व यही वह पल होता है जहाँ संस्कार हार जाते हैं और बाजार जीत जाता है। कई लोग कहते हैं – ह्लहम तो ईएमआई पर खरीद रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है?ह्व पर फर्क यह है कि अब आप उस चीज के मालिक नहीं, बल्कि वह चीज आपकी जेब और मानसिक शांति की मालिक बन गई है। ईएमआई केवल किस्त नहीं, एक अदृश्य जंजीर है जो आत्मसंतोष को बाँध लेती है। महंगी वस्तुएँ कुछ पलों की खुशी देती हैं, पर धीरे-धीरे वही बोझ बन जाती हैं।

मध्यवर्गीय समाज आज सबसे ज्यादा इस झूठी प्रतिष्ठा की होड़ में फँसा हुआ है। वह अपनी असल जरूरतें भूल चुका है, और दिखावे की दुनिया में जी रहा है। वह ह्लकैसा दिखता हूँह्व में उलझ गया है, ह्लमैं क्या हूँह्व यह भूल गया है। दिखावे की संस्कृति ने केवल जेब नहीं, नैतिकता भी खाली कर दी है। अब लोग दूसरों की नजरों में अच्छे दिखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कोई अपनी निजता बेच रहा है, कोई झूठे रिश्ते दिखा रहा है, तो कोई सस्ती लोकप्रियता के लिए मयार्दा छोड़ रहा है। जहाँ कभी पर्दा सम्मान का प्रतीक था, आज वही पर्दा फोटोशूट की सजावट बन गया है।

अब सच्चाई दिखाना पुराना चलन माना जाता है। जो दिखता है वही बिकता है – यही आज की दुनिया का नारा है। पर जो बिकता है, वह सदा टिकता नहीं। दिखावे की चमक थोड़े समय की होती है, पर सच्चाई की रोशनी स्थायी होती है। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है – आपका आत्मसम्मान। उसे कोई बाजार, कोई सेल, कोई ऑफर नहीं खरीद सकता। जरूरतें पूरी कीजिए, लेकिन इच्छाओं को समझदारी से सीमित कीजिए। फोन काम के लिए हो, पहचान के लिए नहीं। सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का माध्यम बने, आत्ममूल्य का मापदंड नहीं। मर्यादा का अर्थ बंदिश नहीं, बल्कि अपनी असल पहचान है।

दिखावे के शोर में सादगी की आवाज ही सबसे प्रभावशाली होती है। अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच और खरीददारी की मानसिकता बदलनी होगी। यह समय हमसे सवाल करता है – क्या हम अपने मालिक हैं या बाजार के गुलाम? क्या हम दिखावे की दौड़ से निकलकर सच्चे आत्मसंतोष की राह पकड़ सकते हैं? सवाल आसान है, पर जवाब कठिन। क्योंकि यह लड़ाई पैसों की नहीं, मानसिकता की है। यह तय करेगा कि हम तकनीक और चमक के बीच रहकर भी इंसान बने रह सकते हैं या नहीं। फोन चाहे किसी का भी हो, बात इंसानियत की होनी चाहिए। जब तक हम अपनी जरूरतों से ज्यादा अपनी असलियत को महत्व नहीं देंगे, तब तक हम बाजार के आईने में अपने ही नकली प्रतिबिंब को देखते रहेंगे। समाज तब आगे बढ़ता है जब वस्तुएँ साधन बनें, साध्य नहीं। अब समय है कि हम खुद को ब्रांड के उपभोक्ता नहीं, मूल्यों के रक्षक बनाएं। क्योंकि बाजार की चमक एक दिन फीकी पड़ जाएगी, पर इंसानियत की रोशनी कभी नहीं।

-प्रियंका सौरभ

नई शिक्षा नीति के मूलस्वरूव का विवेचन करती 'नई शिक्षा नीति और नई हिंदी'

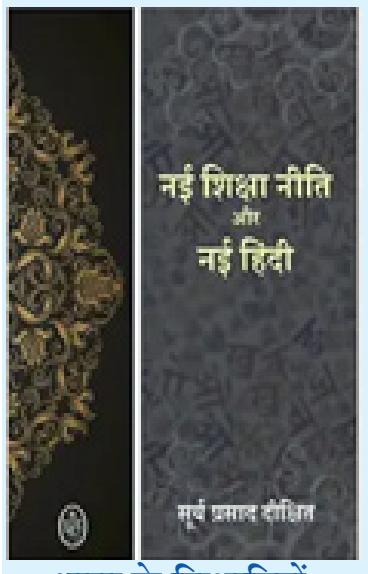

भारत के शिक्षाविदों, विद्यार्थियों, भाषा-प्रेमियों और उन सभी पाठकों के लिए अनिवार्य सैद्धांतिक विमर्श, जो भारतीय शिक्षा की वास्तविक दिशा और हिंदी की भविष्यगत संभावनाओं पर गंभीरता से विचार करना चाहते हैं।

भारतीय शिक्षा-व्यवस्था आज जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां एक ओर सदियों से चला आ रहा औपनिवेशिक ढांचा है और दूसरी ओर उस ढांचे को बदलने राहरी आकांक्षा । इस संक्रमण और रूपांतरण के बीच सूर्य प्र-साद दीक्षित की 'नई शिक्षा नीति और नई हिंदी' एक गंभीर और सार्थक हस्तक्षेप की तरह सामने आती हैं। यहां नई शिक्षा नीति के मूल स्वरूप का विवेचन है, साथ ही हिंदी भाषा की भूमिका को शिक्षा और समाज के व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखकर उसके सांस्कृतिक-सामाजिक निहितार्थों को भी गहराई से रेखांकित किया गया है। भाषा को नई शिक्षा नीति की पूरक एवं प्रेरक मानकर इसे 'नई हिंदी' कहा गया पुस्तक में हिंदी है। इसमें नई शिक्षा नीति के प्रावधानों-लचीले पाठ्यक्रम, शोधोन्मुख दृष्टिकोण, स्नातक शिक्षा की अवधि में वृद्धि, आनलाइन शिक्षण की व्यवस्था और विदेशी विश्वविद्यालयों की शाखाओं की स्थापना पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। लेखक स्वीकार करते हैं कि यह नीति यदि सही ढंग से लागू हो, तो मैकाले की औपनिवेशिक शिक्षा-व्यवस्था का वास्तविक विकल्प बन सकती है, लेकिन इसके लिए 'नई हिंदी' को समयानुकूल रूप में ढालना होगा। यह केवल साहित्य तक सीमित न रहकर शिक्षा, शासन, वाणिज्य और संचार की भाषा बने, राष्ट्र की भावात्मक एकता को सुदृढ़ करे और भारतीय संस्कृति को शिखर पर पहुंचाए। इसके अलावा, शिक्षा की धुरी-प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर लौटकर, उसके आलोक में शिक्षा का कायाकल्प किया जा सकता है। पुस्तक का विश्लेषण गहन, तर्कपूर्ण और अनुभवजन्य है। दीक्षित जी का दृष्टिकोण केवल शैक्षिक नीतियों के प्रावधानों तक सीमित नहीं रहता, वे मानते हैं कि जब तक शिक्षा का माध्यम अपनी मातृभाषाएं नहीं बनेंगी, तब तक शिक्षा का वास्तविक भारतीयकरण संभव नहीं। यहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सापेक्ष नई भाषा-नीति और उसमें भारतीय भाषाओं की भूमिका पर विचार किया गया है। हिंदी को उत्तर-दक्षिण सेतु के रूप में प्रस्तुत करने के साथ-साथ, लगभग डेढ़ हजार वर्षों की समृद्ध हिंदी भाषा-साहित्य पर भी दृष्टि डाली गई है, जहां अनेक महत्वपूर्ण कृतियों और रचनाकारों का उल्लेख मिलता है। यहां मानवतावादी चिंतन धारा के अतिरिक्त वर्तमान में खड़ी चुनौतियों को समग्रता से देखा गया है। 'नई हिंदी' के लिए पुस्तक कई दूरगामी लक्ष्य निर्धारित करती हैं, जैसे- ज्ञान-विज्ञान परक लेखन को बढ़ावा देना, शिक्षा को मूल्यपरक और अनुप्रयोगमुखी बनाना, कौशल विकास और आजीविका के अवसरों का विस्तार करना, आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण और सामाजिक कदाचार का उन्मूलन करना, युवा पीढ़ी में सकारात्मक सोच और सांस्कृतिक आत्मविश्वास जगाना, अध्यात्म, विज्ञान और तकनीक के समन्वय से नई दृष्टि गढ़ना और भारत को सांस्कृतिक तथा बौद्धिक रूप से और सशक्त करना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है।

यह किताब हमें स्वतंत्रता से पहले और बाद के समय की परिस्थितियों की झलक देती है, किताबों, खबरों और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से और भारतीय किसान तथा खेती की कठिनाइयों को हमारे सोच के के द्र में रख देती है। यह सिर्फ किसानों का दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का आईना है। लेखक ने इसे आत्मीय ढंग से अपनी बेटी के लिए लिखा है, ताकि अगली पीढ़ी तथ्यों को समझ सके, जमीनी हकीकत को महसूस करते हुए भविष्य की संवेदनशील और समझदार नीतियों की दिशा में सोच सके और समझ सके कि किसानों की पीड़ा केवल गांव का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे समाज का भविष्य है।

महिलाओं और बेटियों की घटती संख्या

विजय गर्ग

यह एक विचित्र विडंबना है कि पिछले कई दशकों से लगातार स्त्री-पुरुष अनुपात में बढ़ती खाई को लेकर चिंता जताई जाती रही है। इसे रोकने के लिए तमाम जागरूकता अभियानों से लेकर सरकारी कार्यक्रम भी चलाए गए। मगर आज भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की कम या घटती संख्या के प्रति चिंता का स्तर एक ही जगह थम गया लगता है। हालत यह है कि इसके एक मुख्य कारण के रूप में भ्रूण हत्या पर चर्चा होती है, उसे रोकने के लिए नियम-कायदे भी बनाए जाते हैं, लेकिन अब भी इसका सहारा लेकर बेटियों को दुनिया में आने से पहले ही रोक देते हैं। भारत में भ्रूण हत्या मानो आम बात । चली है। जन्म के बाद लड़कियों को लावारिस छोड़ने अथवा झाड़ियों में फेंकने की भी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। तमाम प्रयासों बाद भी भ्रूण हत्या और नवजातों की मौत को रोका नहीं जा सका है। जबकि देश में भ्रूण हत्या से लिंगानुपात लगातार बिगड़ रहा है, जिससे आने वाले समय में सामाजिक असंतुलन बढ़ता ही जाएगा। भ्रूण हत्या ऐसी ई है, जिसके आंकड़े न केवल डरावने हैं, बल्कि किसी भी संवेदनशील व्यक्ति और समाज को झकझोरते भी हैं।

सरकार के आंकड़ों के आधार पर 'प्यू रिसर्च सेंटर' की एक रपट कहती है कि वर्ष 2000 से 2019 तक भारत में कम से कम 90 लाख भ्रूण हत्या हुई। इनमें 186.7 फीसद हिंदुओं (80 फीसद आबादी), 4.9 प्रतिशत सिखों (1.7 फीसद आबादी) और 6.6 फीसद मुसलिमों (14 फीसद आबादी) में दर्ज की गई। हालांकि बेटे को वरीयता देने में अब कमी आई है, फिर देश में गर्भपात जारी हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 0-6 वर्ष आयु वर्ग प्रति एक हजार लड़कों पर 914 लड़कियां थीं। जबकि वर्ष 1991 में यह अनुपात 945 था। भारत में लिंग अनुपात की कोई अच्छी स्थिति नहीं है। स्पष्ट है कि यह भ्रूण हत्या की और ही इशारा करती है। लांसेट की रपट कहती है कि हर वर्ष 2.39 लाख अतिरिक्त बालिका मृत्य से कम) दर्ज । मृत्यु (5 वर्ष कम) दर्ज की जाती हैं, जो मुख्य रूप से उपेक्षा और कुपोषण के कारण होती हैं।

वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो का आंकड़ा बताता है कि देश में वर्ष 2022 में शिशु हत्या के 63 मामले दर्ज किए गए, जिनमें : महाराष्ट्र में सबसे अधिक 25 मामले । कन्या शिशु हत्या 1 के विशिष्ट आंकड़े अलग से नहीं दिए गए। यह संख्या वास्तविकता से बहुत कम हो सकती है, क्योंकि कई मामले उपेक्षा के कारण भुखमरी बता कर दर्ज नहीं होते। असल में कन्या भ्रूण हत्या के आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं, क्योंकि गर्भपात के सभी मामले प्रायः दर्ज नहीं होते। दूसरी ओर नवजात की मौत के मामले भी कम दर्ज होते हैं, क्योंकि इन्हें अक्सर मृत जन्म या प्राकृतिक मृत्यु के रूप दिखाया जाता है। हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में लिंग अनुपात में भारी असंतुलन है। यह स्थिति गंभीर है। उत्तराखंड में 2019 के दौरान 132 गांवों में तीन महीने तक एक भी कन्या का जन्म नहीं हुआ। सरकार बाकायदा कानून पारित कर भ्रूण परीक्षण प्रतिबंध लगा चुकी है। इसके बावजूद हालात नहीं बदले। देश में हजारों क्लीनिक ऐसे हैं, जहां आज भी भ्रूण परीक्षण चोरी-छिपे चल रहा है। राज्य सरकारों के पास इतने

संसाधन नहीं हैं कि सभी क्लीनिकों पर नजर रखी जा सके। इसके लिए आम नागरिकों को जागरूक होना होगा और सरकार की मदद करनी होगी। उधर, लड़कियों को जन्म से पहले मारने की प्रथा अब वहां भी प्रचलित हो रही है, जो अब तक इससे बचे हुए थे जैसी खबरें आ रही हैं, अब जम्मू-कश्मीर में भी स्थिति चिंताजनक है। वहां का श्रीनगर शहर पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की राह पर है। ऐसी ही स्थिति और भी कई शहरों की बन रही है।

लड़कियों के प्रति इस नकारात्मक सोच के गंभीर सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। यह बेहद चिंता का विषय है। बार-बार गर्भपात से स्त्रियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। यदि लड़कियों की संख्या इसी तरह घटती रही, तो आगे चल कर महिलाओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं बढ़ने का अंदेशा है। विवाह के लिए उनका अपहरण किया जाएगा, उनकी इज्जत पर हमले होंगे। ऐसे में यह एक गंभीर स्थिति होगी। कर लड़कियों की कम संख्या उनके सम्मानजनक जीवन जीने के अवसरों कुल मिला को कम कर देगी और उनसे जुड़ी कई कुप्रथाओं भी बढ़ावा देगी। वहीं कई सामाजिक अवधारणाओं के कारण जब वह दिन शुरू मां के गर्भ में यह संघर्ष उसके जीवन के एक बड़े हिस्से को निगल` जाता है इस दुनिया में जीने की इजाजत क्यों न हो। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि कन्या भ्रूण हत्या अब किसी दायरे में सिमटी नहीं रह गई है। । शहरी क्षेत्रों क्षेत्रों और महानगरों में रहने वाले अति आधुनिक भले ही उसे शिक्षित लोग भी गर्भ में ही बालिकाओं की पहचान करा कर उसे खत्म करने में करने में पीछे नहीं हैं। यह बेहद ही दुखद स्थिति है।

लड़कियों की संख्या घटने का एक कारण यह भी है कि सरकार के जनसंख्या नियंत्रण अभियानों में कई कमियां रही हैं। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सरकार ने दो से अधिक बच्चों वाले माता-पिता को कुछ अधिकारों से वंचित कर दिया है। जैसे, तीन बच्चों की मां को की मां को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। यदि वह कर्मचारी है, तो है, तो कई तरह की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसका सीधा असर महिलाओं के प्रति सामाजिक धारणा और संकीर्ण होने के रूप में सामने आता है। यह दुखद सच है कि लड़कियों के अनुपात में गिरावट के कारण कई ग कई राज्यों में युवाओं को में कई गरीब इलाकों के निर्धन परिवारों को विवाह के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। ऐसी खबरें आम रही आम रहा है, जिनम की लड़कियों को खरीद कर शादी करने के बारे में चिंता जताई जाती है। दलालों के जरिए खरीद- -फरोख्त का यह सिलसिला दिनों-दिन बढ़ रहा है। यह निराशाजनक है कि इसे रोकने के लिए किसी भी स्तर पर ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा जा रहा है।

जो समाज के लिए खतरा है, बल्कि समाज के संतुलन को भी बिगाड़ रहा है। इसे रोकने के लिए हर परिवार को जागरूक करना होगा, ताकि वे बेटियों को समान अधिकार और सुरक्षा देने की अहमियत को समझ सकें। हमें हर घर तक यह संदेश पहुंचाना होगा कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि देश और समाज की ताकत हैं। हमें उनके जन्म का उत्सव मनाना होगा और उनके शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। कोई दोराय नहीं कि भ्रूण हत्या से लिंगानुपात बिगड़ रहा है, जिससे आने वाले समय में सामाजिक असंतुलन बढ़ जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि कन्या शिशु का स्वागत करें और उनका पालन-पोषण तथा शिक्षा सुनिश्चित करें। इस तरह की सोच से ही हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। हमें इस दिशा में एकजुट होकर काम करना होगा, ताकि हर बेटी सुरक्षित माहौल में पल कर आगे बढ़ सके।

मलोट पंजाब

अन्नदाता की वास्तविकता से रूबरू कराती 'किसानी की कहानी'

प्रति दिन आम नागरिक अपनी थाली भरते हैं, पर शायद ही कभी सोचते हैं कि यह कितने संघर्ष और पीड़ा की कीमत पर मिली है। वही किसान, जिसकी मेहनत से हमारी दुनिया जिंदा है, अक्सर भूख, कर्ज और निराशा में जूझता है। जब किसान की जिंदगी अंधेरे में हो, तब हमारा चैन से जीना एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं । सोरित गुप्तो की 'किसानी की कहानी' इसी भ्रम को तोड़ती है। 'हम भारत के किसान'- शुरूआत इसी यथार्थ से होती है, जहां जुलाई 2004 की द हिंदू समाचार पत्र की रिपोर्ट में जना रेड्डी और उनके परिवार की पीड़ा एक ऐसी त्रासदी मौजूद है जो भीतर तक चुभती है और आखिरकार जना रेड्डी की मौत पर जाकर ठहरती है। पुस्तक बताती है कि किस प्रकार अंग्रेजों ने एक समृद्ध और औद्योगिक देश को एक गरीब और कृषि प्रधान देश में बदल दिया। ब्रिटिश राज में महाजनों का अत्याचार, विभाजन में कृषि क्षेत्र को हुआ नुकसान, अलग-अलग राज्यों में हुए भूमि सुधार और कृषि परिस्थितियां, हरित क्रांति से मिली सीख, 1991 में तत्कालीन सरकार द्वारा दो बार भारतीय मुद्रा का दाम घटाना, निजीकरण, व्यापारिक फसलों का उत्पादन, किसानी और जलवायु परिवर्तन जैसे तमाम मुद्दे कामिक की शैली में सामने आते हैं, जिसने कठिन विषयों-किसान आत्महत्या, कृषि संकट, खाद्य सुरक्षा और राजनीतिक जटिलताओं को सरल और समझने योग्य बना दिया है। अंतरराष्ट्रीय घटनाओं और नीतिगत बदलावों को जोड़ते हुए यह रचना पाठक को हर घर की मेज तक ले आती है।

यह किताब हमें स्वतंत्रता से पहले और बाद के समय की परिस्थितियों की झलक देती है, किताबों, खबरों और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से और भारतीय किसान तथा खेती की कठिनाइयों को हमारे सोच के केंद्र में रख देती है। यह सिर्फ किसानों का दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का आईना है। लेखक ने इसे आत्मीय ढंग से अपनी बेटी के लिए लिखा है, ताकि अगली पीढ़ी तथ्यों को समझ सके, जमीनी हकीकत को महसूस करते हुए भविष्य की संवेदनशील और समझदार नीतियों की दिशा में सोच सके और समझ सके कि किसानों की पीड़ा केवल गांव का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे समाज का भविष्य है। यहां तथ्य रोचक और संवादात्मक ढंग से प्रस्तुत हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछली सरकारों की उदासीनता के बावजूद, आज की सरकार ने किसानों के प्रति गहरी संवेदनशीलता दिखाई है। मौजूदा योजनाओं ने स्पष्ट रूप से किसानों की कठिनाइयों में कमी लाने में मदद की है, लेकिन इसके बावजूद, किसानों के लिए जो भी प्रयास किए जाएं, वह हमेशा कम ही रहेंगे, क्योंकि किताब की चेतावनी स्पष्ट है- 'यदि किसान नहीं रहेंगे, तो हमारी थालियों से भोजन गायब हो जाएगा।' निस्संदेह, 'किसानी की कहानी' एक चेतावनी है, साथ ही एक दर्पण भी, जो हमें अपने अन्नदाता की वास्तविकता से रूबरू कराती है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादक: पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com